भारतीय रेल बजट भाषण 2016-17

25 फरवरी, 2016 को 2016-17 के लिए रेल बजट पेश करते हुए श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु का भाषण।

अध्यक्ष महोदया,

1. अब मैं माननीय सदन के समक्ष 2016-17 के लिए भारतीय रेल का अनुमानित आय और व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता हूँ।

2. शुरुआत में, मैं आपको अपने कुछ निजी अनुभव सुनाना चाहता हूँ। भारत के रेल मंत्री के नाते मैं बहुत से स्थानों पर जाता हूँ और सभी क्षेत्रों के बहुत से लोगों से मिलता रहता हूँ। एक बार मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन गया, तो यह देखकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि कुछ महिलाएं स्टेशन की सफाई में व्यस्त थीं। स्टेशन एकदम साफ दिख रहा था। मुझे देखकर एक महिला मेरे पास आई और उनके गैर-सरकारी संगठन (NGO) को इस स्टेशन को गोद लेने के लिए मुझे धन्यवाद दिया।। वह पिछले पांच महीनों से महीने में एक दिन स्वेच्छा से इस स्टेशन की साफ-सफाई में लगाती हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए काम करने में अपने इस छोटे से योगदान पर उन्हें बेहद खुशी है।

3. दूसरी घटना में, रेल सुरक्षा बल के एक इंस्पेक्टर श्री आलोक तिवारी, जो रेलवे बोर्ड के सोशल मीडिया सेल में हैं, ने अपनी भावनाएं साझा कीं। उनकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर मदद के लिए यात्रियों के अनुरोध पर कार्रवाई करना है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्हें अनुभव हुआ है कि कैसे उनके द्वारा किए गए छोटे-छोटे काम भी यात्रियों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं। वह इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थे और भारतीय रेल में काम करने पर गर्व महसूस कर रहे थे।

4. अध्यक्ष महोदया, इन जैसे लोग ही भारत और भारतीय रेल की असली आत्मा हैं और इसीलिए यह केवल मेरा बजट नहीं है। यह बजट रेल परिवार के प्रत्येक सदस्य की अभिलाषा का प्रतिबिंब है। यह भारत के आम नागरिक की आकांक्षा का बजट है जो मेरे

साथ अपने विचार साझा करने के लिए न केवल मुझे पत्र लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में मुझसे मिल भी रहे हैं। यह ऐसा बजट है जो संसद के मेरे सहयोगियों, अनेक उद्योग संघों, यात्री संघों, मीडिया और व्यावहारिक रूप से समाज के सभी वर्गों के साथ विचारों की रचनात्मक भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इन सबसे ऊपर इस बजट की प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन और नेतृत्व है जिन्होंने भारतीय रेल को दिल खोलकर प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने एक बार कहा था, *रेलवे को* ***'भारत की प्रगति और आर्थिक विकास की रीढ़ बनाना मेरा विजन है'।*** हम उनके इस विजन को साकार करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर ग्राहक के अनुभव में सुधार, राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार के सृजन और आर्थिक प्रगति में अग्रणी होना है तथा भारत की इस सबसे बड़ी संस्था में बदलाव लाकर मिसाल पेश करना है।

"यात्री की गरिमा, रेल की गति-राष्ट्र की प्रगति"।

यह बजट बदलाव की यात्रा का, प्रतिदिन लाखों जिंदगियों को प्रभावित करते हुए हमारे देश की यात्रा का दस्तावेज होगा। ।

चुनौतियों से निपटना - हमारी रणनीति

5. यह समय चुनौतियों से भरा है, शायद सबसे मुश्किल भी। हमारे सामने दो प्रमुख चुनौतियां हैं, जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर हैं; अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धीमी प्रगति और 7वें वेतन आयोग और बढ़े हुए उत्पादकता संबद्ध बोनस का प्रभाव। इसके अलावा, परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी, जो

1980 के 62% से गिरकर 2012 में 36% हो गई थी, का भी हम पर दबाव बना हुआ है। मुझे इस समय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं:

विपदाएं आती हैं आएं, हम न रूकेंगे, हम न रूकेंगे
आघातों की क्या चिंता है? हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे।

6. भारतीय रेल एक ऐसा संगठन है, जो अपने कर्मचारियों के असीम धैर्य और समर्पण के कारण समय की कसौटी पर खरा उतरा है। परन्तु चुनौतियों से भरे इस समय में बरसों से चले आ रहे कार्य करने के तरीके और प्रकृति में बदलाव जरूरी है। पिछले वर्ष, मैंने रेलों के लिए मध्यावधि विज़न प्रस्तुत किया था, जिससे हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे है। अब हमें इस संस्था के **पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और इसमें पुनरूद्धार** की आवश्यकता है। हमें एक नए नजरिए, काम करने के नए तरीके को अपनाने की जरूरत है- ***"चलो, मिलकर कुछ नया करें"।***

7. हमारी कार्य योजना के जिन तीन स्तंभों के बारे में मैं आज बता रहा हूँ, वे इस नई विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं:-

(क) **नव अर्जन:** अब तक भारतीय रेल ने राजस्व बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाने पर ही विशेष जोर दिया है। हम इसे बदलना चाहते हैं और परिवहन के क्षेत्र में हमारे हिस्से को दोबारा पाने के लिए हम मालभाड़ा नीतियों पर अपनी परंपरागत सोच को बदलना चाहते हैं। हम राजस्व के नए स्रोतों का दोहन करेंगे ताकि प्रत्येक दृश्य या अदृश्य परिसंपत्ति, को अधिकाधिक भुनाया जा सके।

(ख) **नव मानक**: अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए खर्च होने वाले एक-एक रुपए की पुन: जांच की जाएगी। हम आगामी वर्ष में वित्तीय दृष्टि से 'शून्य आधारित बजट प्रक्रिया' की अवधारणा अपनाएंगे। हम अपने कार्यकुशलता के मानदंडों और खरीद प्रक्रियाओं में सुधार करके उन्हें अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के समकक्ष बनाएंगे। हम अपने प्रत्येक क्रिया कलाप को कुशलता से पूरा करेंगे और परिणाम भी प्राप्त करेंगे।

(ग) **नव संरचना**: हमें समस्याओं को सुलझाने के परंपरागत तरीकों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। हमारे निर्णय और कार्यों पर *सहकारिता, सहयोग, सृजनात्मकता और संवाद* की स्पष्ट छाप होनी चाहिए। भारतीय रेल में यह बदलाव लाने के लिए हम सभी प्रक्रियाओं, नियमों और ढांचों की दोबारा जांच करेंगे। हम अपनी अंदरूनी ताकतों, विविध प्रतिभाओं और भरपूर अनुभव का प्रयोग करेंगे ताकि और मजबूत होकर उभरें।

नव उमंग

नव तरंग

जीवन का नव प्रसंग

नवल चाह

नवल राह

जीवन का नव प्रवाह

- श्री हरिवंश राय बच्चन

वित्तीय निष्पादन

8. 2016-17 में 7वें वेतन आयोग का तात्कालिक प्रभाव भी शामिल करने के बाद, परिचालन अनुपात 92% रहने की आशा है, जबकि चालू वर्ष में इसके 90% रहने की संभावना है। यह उल्लेखनीय है कि छठे वेतन आयोग के प्रभाव के कारण 2008-09 में साधारण संचालन व्यय में 32.5% की वृद्धि हुई थी, जबकि हम 2016-17 के लिए साधारण संचालन व्यय को 11.6% तक सीमित रखने का लक्ष्य रख रहे हैं। ऐसा काफी हद तक लागत को इष्टतम करने और अगले वर्ष के लिए नवीन उपायों के जरिए राजस्व में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई योजना के कारण संभव हुआ है। हमने इस दिशा में एक छोटी-सी शुरूआत की है, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष बजट अनुमानों से 8,720 करोड़ रु. की बचत होगी, जिससे राजस्व की अधिकांश कमी को पूरा कर लिया जाएगा। हमने दीर्घकालिक करारनामों पर हस्ताक्षर करके, इन्वेंटरी को रखने की लागतों को कम करके और मितव्ययता अभियान चलाकर कर्षण के लिए खरीदी गई बिजली की लागत में

भारी कमी की है। अगले वर्ष हम लागत को इष्टतम बनाने के लिए कई गुणा कड़े उपाय अपनाएंगे। भारतीय रेल में पहली बार डीज़ल और बिजली जैसी कोटियों में ठोस और कड़े नियोजन के जरिए पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कमी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और आगे बताए जाने वाले विभिन्न उपायों के साथ हमें आशा है कि अगले वर्ष हम 1,84,820 करोड़ रु. का राजस्व जुटा पाएंगे, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य से 10.1% अधिक है। 2015-16 के लिए वित्तीय निष्पादन विवरण और 2016-17 के लिए आय और व्यय का बजट अनुमान अनुलग्नक -1 पर रखा है।

निवेश और संसाधन

निवेश

9. हमने पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया है ताकि संगठन के पिछले भारी बैकलॉग को समाप्त किया जाए और मौजूदा तथा भावी जरूरतों को पूरा किया जाए। हमने वर्षों पुरानी प्रक्रिया संबंधी बाधाओं का निरीक्षण किया है और कार्यात्मक स्तर पर प्रभावपूर्ण ढंग से शक्तियों का प्रत्योजन किया है। इसके परिणामस्वरूप, इस वर्ष की अंतिम तिमाही में पूंजी व्यय की दर में काफी वृद्धि हुई है और आशा है कि भविष्य में भी इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हम पूंजीगत व्यय के लिए इस नए दृष्टिकोण को जारी रखेंगे। हम वर्ष 2009-14 की अवधि में 48,100 करोड़ रु. के औसत पूंजीगत व्यय और 8% प्रतिवर्ष की औसत वृद्धि से आगे निकलकर उल्लेखनीय प्रगति करने में सफल हुए हैं। इस वर्ष, हमारा निवेश पिछले वर्ष के औसत का लगभग दोगुना होगा। ऐसा उछाल पहले कभी हासिल नहीं हुआ। वर्ष 2016-17 में पूंजीगत योजना के लिए 1.21 लाख करोड़ रु. रखे गए हैं।

10. हमें बड़े निवेश के लिए कारोबार को आम नजरिए से हटकर देखने और फंड जुटाने तथा परियोजना निष्पादन के नए-नए तरीके ढूंढने के लिए सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है। देश के अवसरंचनात्मक विकास में भारतीय रेल अग्रणी रहेगी, चाहे वह राज्यों के साथ साझा उद्यम हो, पीपीपी के लिए नए ढांचे का विकास हो, रु. बॉंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नजर रखना हो या बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ

संपर्क करना हो। भारतीय रेल देश में अवसंरचनात्मक विकास में अग्रणी रहेगी। हमने पहली बार स्वीकृत निर्माण कार्यों की 'पिंक बुक' में राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा शुरू की जा रही भागीदारी परियोजनाओं की एक सूची शामिल की है। रेलवे में निवेश किए गए एक रुपए में इतनी क्षमता है कि समग्र अर्थव्यवस्था में 5 रुपए की वृद्धि कर सके। रेलवे में इस बढ़े हुए निवेश का आर्थिक विकास पर जो प्रभाव होगा वह अभूतपूर्व है। इससे एक आधुनिक और कुशल रेल प्रणाली का विजन साकार होगा।

विज़न

11. हमें भारत के नागरिकों को एक ऐसी रेल सेवा मुहैया करानी है जिस पर वे गर्व कर सकें- सीमित क्षमता और गति के अवरोधों से मुक्त सेवा, ऐसी सेवा जो कुशल और लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली हो, ऐसी सेवा जो शानदार हो और यादगार हो, जहां मेरे देश के लोग आराम महसूस करें, जहां हमारे पास रेलवे के सभी क्षेत्रों के कार्यकलापों के लिए काफी विकल्प हों और समूची रेलवे प्रणाली कार्य कर सके और पर्यावरण अनुकूल हो अर्थात् ऐसी प्रणाली जो अपनी वित्तीय और अन्य जरूरतें, पूरी करने में सक्षम हो।

12. हमें आशा है कि हम वर्ष 2020 तक आम आदमी की लंबे समय से चली आ रही आशा को पूरा कर सकेंगे:

    - गाड़ियों में आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध होना।
    - विश्वसनीय सेवा प्रतिबद्धता के साथ माल गाड़ियों को समय-सारणी के अनुसार चलाना।
    - संरक्षा रिकॉर्ड में पर्याप्त सुधार के लिए उच्चस्तरीय तकनीक।
    - बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त करना।
    - समय पालन लगभग 95% तक पहुंचाना।

- मालगाड़ियों की औसत गति को 50 किमी. प्रति घंटे और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत गति को 80 किमी. प्रति घंटे तक बढ़ाना।
- स्वर्णिम चतुर्भुज पर सेमी हाई स्पीड गाड़ियां चलाना।
- गाड़ियों से मल-मूत्र के सीधे डिस्चार्ज को समाप्त करना।

13. मैं, डॉ. विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति सहित विभिन्न समितियों का आभारी हूँ, जिनकी सिफारिशों ने हमारे विज़न का आधार रहा है। उनकी अनेक सिफारिशों का, पहले ही मेरे बजट भाषण का अंग होने के कारण, तेजी से कार्यान्वयन हुआ है जबकि अन्य में तेज प्रगति है।

उपलब्धियां

पिछला वर्ष

14. हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि तेजी, कुशलता और पूरी पारदर्शिता के साथ विज़न को वास्तविकता में बदला जाए। अपना दूसरा बजट भाषण आरंभ करते हुए मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि यह अवसर केवल नई योजनाओं की घोषणाओं का ही नहीं है बल्कि पिछले वर्ष के कार्यों को परखने का भी है। जिम्मेदारी सदा से ही सार्वजनिक जीवन का सिद्धांत रही है।

15. मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि पिछले वर्ष की गई 139 घोषणाओं पर कार्रवाई आरंभ की गई है। पहली बार, कार्यान्वयन रपट इस भाषण के साथ अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है। अध्यक्ष महोदया, मैं पहले इस वर्ष के दौरान की गई कुछ मुख्य पहलकदमियों की प्रगति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

परियोजना निष्पादन

16. मैं सदन को सहर्ष सूचित करता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक रेल परियोजनाओं को अब फंड मिलने का पूरा भरोसा है और ये अगले 3-4 वर्षों में पूरी हो जाएंगी। संस्थागत वित्तपोषण के माध्यम से हमने हमारी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने का नया उपाय ढूंढा है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने बहुत ही अनुकूल शर्तों पर पांच वर्षों में 1.5 लाख

करोड़ रु. का निवेश करने की सहमति दी है। हम रेल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बहुपक्षीय सहयोग से एक निधि भी स्थापित करना चाहते हैं।

17. चालू वित्त वर्ष के दौरान, परियेाजना निष्पादन में हम नए बैंचमार्क स्थापित कर पाए हैं। हम 2,500 किमी. अतिरिक्त बड़ी लाइन चालू करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य से भी आगे निकल जाएंगे। यह पिछले वर्ष से लगभग 30% अधिक होगा। अगले वर्ष हमारी 2,800 किमी. रेलपथ चालू करने की योजना है।

18. इस वर्ष हमने अपना मानदंड 'लाइन का निर्माण पूरा करना' से बदलकर 'लाइन चालू करना' कर दिया है। "लाइन का निर्माण पूरा करना" शब्द भ्रमित करने वाला है, यह मात्र कागजी सच्चाई है। जब तक लाइन चालू नहीं की जाती, तब तक उसका उपयोग नहीं हो सकता। मैं सम्माननीय सदन को गर्व के साथ सूचित करता हूँ कि पिछले 6 वर्षों के लगभग 4.3 किमी. प्रतिदिन के औसत के मुकाबले हम लगभग 7 किमी. प्रति दिन की रफ्तार से बड़ी लाइन चालू करने में सफल हुए हैं। यह गति 2017-18 में लगभग 13 किमी. प्रति दिन तथा 2018-19 में लगभग 19 किमी. प्रति दिन तक बढ़ेगी और 2017-18 में लगभग 9 करोड़ श्रम दिवस तथा 2018-19 में 14 करोड़ श्रम दिवस के रोजगार का सृजन करेगी।

विद्युतीकरण

19. यह सिद्ध हो चुका है कि बिजली कर्षण अधिक पर्यावरण हितैषी होने के अलावा अधिक किफायती भी है। सामान्य कामकाज की रीति के अनुसार, हमें आवश्यक विद्युतीकरण पूरा करने में 10 से 15 साल लगेंगे, जिसे आगामी कुछ वर्षों में पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। हम वित्तपोषण और परियोजना प्रबंधन की अभिनव विधियों तथा ऊर्जा मंत्रालय के साथ भागीदारी के माध्यम से इस प्रक्रिया में कई गुणा तेजी लाएंगे। हम एक बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे, जहां सरकारी राजकोष पर दबाव को कम करने के लिए, विद्युतीकरण से शुद्ध बचत पूँजीगत व्यय का वित्तपोषण करने में हमें समर्थ बनाएगी। इस साल हम 1,600 किलोमीटर को चालू करना चाहते हैं जो अभी तक का सर्वाधिक है। अगले वित्त वर्ष में, हमने रेल विद्युतीकरण के लिए परिव्यय की व्यवस्था को लगभग 50% बढ़ाया है और 2,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

समर्पित माल गलियारा

20. समर्पित माल गलियारा परियोजना, जो देश में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है, गति पकड़ रही है। इस सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यह वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले, सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों के लगभग सभी ठेके दिए जा चुके होंगे। मेरे द्वारा कार्यग्रहण करने के बाद, 24,000 करोड़ रुपये मूल्य के ठेके दिए गए हैं, जबकि पिछले 6 वर्ष में 13,000 करोड़ रुपये मूल्य के ठेके दिए गए थे।

21. माल यातायात व्यवसाय के तीव्र विस्तार पर बल को देखते हुए, सवंर्धित यातायात के लिए नए समर्पित माल गलियारों का निर्माण करना अनिवार्य है जिसके अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए परिणामी लाभ होंगे। निम्नलिखित फ्रेट कॉरिडोरों यथा दिल्ली को चेन्नै से जोड़ते हुए उत्तर-दक्षिण, खड़गपुर से मुंबई को जोड़ते हुए पूर्व-पश्चिम और खड़गपुर से विजयवाड़ा को जोड़ते हुए पूर्व तट को शुरू करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं की रूपरेखा, सौंपने और सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित नवीन वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से एक समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन के लिए इन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

पोर्ट कनेक्टिविटी

22. देश के आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्बाध लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने के वास्ते पत्तन संपर्क व्यवस्था एक महत्वपूर्ण घटक है। पिछले साल हमने एक तटीय पत्तन संपर्क कार्यक्रम शुरु किया था। इस सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि टूना पत्तन खोल दिया गया था और जयगढ़, दीघी, रेवास और पारादीप के पत्तनों के लिए रेल संपर्क व्यवस्था की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के लिए, हम नारगोल और हाजिरा के पत्तनों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रस्ताव रखते हैं। हमारे पत्तनों तक कनेक्टिविटी मुहैया कराने की तात्कालिक जरूरत पर विचार करते हुए, हम 7,517 किमी तट रेखा पर किसी भी प्रकार की भागीदारी के प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।

पूर्वोत्तर

23. पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बेहतर संपर्क व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हमने असम में चिर-प्रतीक्षित बड़ी लाइन पर लमडिंग-सिलचर खंड को खोला है और इस प्रकार बराक घाटी को शेष देश के साथ जोड़ दिया गया है। हम त्रिपुरा की राजधानी, अगरतला को भी बड़ी लाइन नेटवर्क पर लाए हैं। मिजोरम और मणिपुर राज्य भी, कटखल-भैराबी और अरुणाचल-जीरीबाम की आमान परिवर्तन परियोजनाएं जल्दी ही खोल दिए जाने पर, देश के बड़ी लाइन मानचित्र पर आ जाएंगे।

जम्मू एवं कश्मीर

24. जम्मू एवं कश्मीर में, कठिन भूभाग और अनिश्चित भूविज्ञान के बावजूद, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का कटरा-बनिहाल खंड संतोषजनक प्रगति कर रहा है और कुल 95 किलोमीटर में से 35 किलोमीटर सुरंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। जालंधर-जम्मू लाइन का संकुलन दूर करने के लिए, जो इस घाटी के लिए एक महत्वूपर्ण लिंक है, कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। दो पुलों का दोहरीकरण मार्च 2016 में खोल दिया जाएगा और अन्य दो पुलों को 2016-17 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मेक इन इंडिया

25. मेक इन इंडिया पर हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता का अनुकरण करते हुए, भारतीय रेल लगभग 40,000 करोड़ रुपये की क्रयादेश बही के साथ दो रेलइंजन कारखाने लगाने के लिए बोलियों को अंतिम रूप देने में समर्थ हुई। ये कारखाने अनेक फलती-फूलती लघु और मझौली अनुषंगी इकाइयों के एक पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करेंगी, जो ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़ जाएगा। ये न केवल बिहार राज्य में बल्कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं में वृद्धि करेगा। हमने एक ऐसी बिडिंग प्रक्रिया प्रारंभ की थी जो पूर्णतया पारदर्शी थी और प्राप्त हुई दरें अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक थीं।

26. हमने राजधानी और शताब्दी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले रेलगाड़ी सेटों के विनिर्माण, आपूर्ति और अनुरक्षण के लिए सादृश्य बोली प्रक्रिया आरंभ की है। वर्तमान खरीद को 30% बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

भविष्य के लिए क्षमता निर्माण

27. पिछले एक साल में, हमने भारतीय रेल के संकल्पित त्वरित प्रगति हेतु तत्परता सुनिश्चित करने के लिए संगठन की क्षमता का निर्माण करने के वास्ते अनेक उपाय किए हैं। इस कवायद के फलस्वरूप पूँजीगत व्यय का संवर्धित अवशोषण और परियोजना स्वीकृति चक्र का न्यूनीकरण हुआ है।

पारदर्शिता

28. पारदर्शिता हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारतीय रेल का मिशन अपने समस्त कामकाज में 100 प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। 2015-16 में हमने ऑनलाइन भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और अब सभी पदों के लिए इस प्रकिया का प्रतिरूपण किया जा रहा है। हमारे दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सोशल मीडिया को भी एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्यों के लिए खरीद सहित सभी प्रकार की खरीद ई-प्लेटफॉर्म पर की जा रही हैं। हम कागज रहित प्रबंधन व्यवस्था को अपनाकर एक नए जमाने को लाना चाहते हैं, जहां न केवल बोलियां ऑनलाइन आमंत्रित की जाएंगी बल्कि एक निविदा दिए जाने तक समस्त प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक विधि से संपन्न की जाएगी। हमने उपर्युक्त के लिए परीक्षण संचालन पूरा कर लिया है और अगले वित्त वर्ष में अखिल भारतीय आधार पर इसका लोकार्पण करना चाहते हैं।

शासन

29. कार्यात्मक स्तर पर सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मैंने निविदा और प्राक्कलन संबंधी सभी शक्तियों का क्षेत्रीय रेलों को प्रत्यायोजित कर दिया है। बहरहाल, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप, हम यह सुनिश्चित करने में समर्थ हुए हैं कि परियोजनाएं 6-8 माह की अवधि के अंदर स्वीकृत हो जाएं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पहले 2 से अधिक साल लग जाया करते थे। अधिक प्रत्यायोजन के साथ अधिक जवाबदेही आती है और इस नई संस्कृति को स्थापित करने के

लिए, महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों के लिए मुख्य परिणाम क्षेत्रों (केआरए) को परिभाषित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रगति का स्पष्ट पता चल जाएगा, जिनके आधार पर अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कार्यप्रदर्शन और मध्यावधि कोर्स करेक्शन के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित होगी।

30. हमने कुछ क्षेत्रीय रेलों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कार्यप्रदर्शन पैरामीटरों के संबंध में परिमाणात्मक लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित थे। इससे निर्दिष्ट रेलवे की ओर से उसके लक्ष्यों को पूरा करने में सुदृढ़ प्रतिबद्धता सुनिश्चित हुई। अगले साल हम सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए ऐसा करने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा

31. हमने अपनी कार्य प्रणालियों में कुशलता लाने की दृष्टि से अपनी आंतरिक लेखा प्रणालियों का पुनर्गठन भी किया है। विशेषज्ञता प्राप्त टीमों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में रेलवे के कामकाज की जांच करने की आज्ञा दी गई है ताकि अक्षमता का पता लगाया जा सके और अपव्यय को रोका जा सके। सभी क्षेत्रीय रेलों को वर्तमान वर्ष में ऐसी दो रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। आंतरिक जांच टीमों की व्यावसायिक कुशलता के लिए आईटी आधारित आंतरिक जांच तंत्र से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

साझेदारियां

32. मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय में रेल आधारित परियोजनाएं शुरु करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों का सृजन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय रेलवे के स्वामित्व की साझेदारी, सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत बनाने के लिए नई संभावनाओं को खोलेगा, परियोजना के निष्पादन के लिए प्रबंधन बैंडविड्थ का संवर्द्धन करेगा और राज्यों को संयुक्त रूप से उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए मार्ग उपलब्ध कराने में समर्थ बनाएगा। हमें 17 राज्यों से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिनमें से 6 समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस वर्ष हमने बजट प्रलेखों में लगभग 5,300 कि.मी. पर लगभग 92,714 करोड़ रुपये मूल्य के 44 नए भागीदारी कार्यों का उल्लेख किया है।

33. हमने अभिनव वित्तपोषण के माध्यम से परियोजना निष्पादन की गति में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय, सेल और एनटीपीसी के साथ भी साझेदारियां की हैं।

ग्राहक इंटरफेस

34. आम आदमी हमेशा ही हमारी सभी पहलकदमियों का फोकस रहा है। यह ग्राहक अभिमुख कार्यों के लिए एक अभूतपूर्व साल था।

संवाद और फीडबैक

35. जब हमने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक फीडबैक और शिकायत निवारण तंत्र में तब्दील किया तो ग्राहक की जरूरतों के प्रति भारतीय रेल की प्रत्युत्तरशीलता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इसके अलावा, हमें सीधे यात्रियों से फीडबैक लेने के लिए एक समर्पित आई.वी.आर.एस. प्रणाली स्थापित की है। यात्रियों से इन्पुट लेने के लिए रोजाना 1 लाख से अधिक टेलीफोन किए जाते हैं। इन सभी पूर्वोपायों के साथ, हम ग्राहक को 'मुखर' करने में समर्थ हुए हैं जो न केवल सुनी जाती है बल्कि उस पर कार्रवाई भी की जाती है। ये चैनल न केवल फीडबैक मांगने के लिए अपितु चिकित्सीय देखभाल, यात्रियों खासतौर पर महिलाओं की संरक्षा, और मानवीय देखभाल के अन्य पहलुओं को भी उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्होंने स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में स्वच्छता पर निगरानी रखने में भी हमारी मदद की है। आज आम यात्रियों और रेलवे के बीच कोई अवरोधक नहीं है।

यात्रा को आरामदेह बनाना

36. हमने रेलगाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक श्रृंखलावार उपाय किए हैं। इस प्रयास में, हमें एमपीएलएडी और सीएसआर से निधि के जरिए सहयोग मिला है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 124 संसद सदस्यों ने यात्री सुविधाओं के लिए अपना योगदान दिया है। में इस सहायता के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमें आगामी वर्षों में भी उनका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। अर्थात्:

- लोकप्रिय मार्गों पर 884 सवारी डिब्बों का स्थायी आधार पर संवर्धन करके 65,000 से अधिक शायिकाओं का सृजन किया है।

- रेलवे स्टेशनों पर 2,500 वाटर वैंडिंग मशीनें लगाई हैं, सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट दिए हैं, सभी नए गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों में कूड़ेदान उपलब्ध कराए हैं, विश्रामगृहों की ऑनलाइन बुकिंग सक्षम बनाई है।
- स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए मैकेनाइज्ड लांड्रियों को बढ़ाया है। अब चुनिंदा स्टेशनों पर सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए डिस्पोज़ेबल बिस्तर उपलब्ध हैं।
- आधुनिक साज-सज्जा वाले सवारी डिब्बों के साथ एक नई रेलगाड़ी, 'महामना एक्सप्रेस' शुरु की है।

स्वच्छता

37. स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के हमारे मिशन के अनुसरण में, सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष रहा है कि:

- यह वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले रेलगाड़ियों में 17,000 जैव-शौचालय और 475 रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त शौचालय उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- दुनिया का सर्वप्रथम जैव-निर्वात शौचालय भारतीय रेल द्वारा तैयार किया गया है और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में प्रयोग किया जा रहा है।
- 74 अतिरिक्त रेलगाड़ियों को ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा के अंतर्गत डाला गया है और अन्य 400 को जल्दी ही डाला जाएगा, जिससे इस योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों की कुल संख्या 1,000 हो जाएगी।

समयपालन में सुधार लाना

38. अनेक दशकों से यात्री रेलगाड़ियों का समयपालन निष्पादन चिंता का विषय रहा है। हमारा एक खुला नेटवर्क है, जिसके फलस्वरूप मानवों और जानवरों द्वारा निरंकुश अनाधिकार प्रवेश किया जाता है। संकुलित रेलपथ, टर्मिनल क्षमता की तंगी और परिसंपत्तियों की खराबी के कारण यह समस्या और गंभीर बन जाती है। सबसे प्रभावित खंड गाजियाबाद से मुगलसराय खंड बरास्ता इलाहाबाद और कानपुर है, जो तीन क्षेत्रीय रेलों में फैला हुआ है

जिससे पूरे नेटवर्क के समग्र समयपालन पर प्रभाव पड़ता है। हमने अपने निष्पादन में सुधार लाने के लिए इस खंड पर गाड़ी परिचालन ऑडिट आरंभ किया है। कुछ सुधार पहले से ही दृष्टिगोचर हैं और क्षमता संवर्धन से मध्यावधि में विलंब में और कमी आएगी।

39. आंतरिक कारणों के अलावा, यहां अनेक बाहरी कारण भी हैं जैसे कि रेलपथों पर आंदोलन जिनके फलस्वरूप समयपालन की हानि होती है। मैं इस अवसर पर अपने साथी नागरिकों से इससे परहेज करने की अपील करता हूँ क्योंकि इससे न केवल राष्ट्र की बल्कि यात्रियों के रूप में उनको भी नुकसान होता है।

टिकटिंग

40. पिछले साल मैंने अनारक्षित यात्रियों को कतारों में लंबा समय लगाए बिना टिकट खरीदने में समर्थ बनाने के लिए 'ऑपरेशन पांच मिनट' की घोषणा की थी। इस परिप्रेक्ष्य में, हमने इनकी शुरुआत की है:

- 1,780 आटोमैटिक टिकट वैंडिंग मशीनें और 225 कैश-कॉयन और स्मार्ट कार्ड चालित टिकट वैंडिंग मशीनें
- ई-टिकटिंग मशीनों की क्षमता को 2000 टिकट प्रति मिनट से बढ़ाकर 7,200 टिकट प्रति मिनट और एक ही समय पर 1,20,000 उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकते हैं जबकि पहले केवल 40,000 ही कर सकते थे।
- अनारक्षित और प्लेटफार्म टिकटें खरीदने के लिए मोबाइल बेस्ड एप तथा यूटीएस और पीआरएस टिकटों की कैशलेस खरीदारी के लिए गो इंडिया स्मार्ट कार्ड योजना।

सामाजिक दायित्व

41. दिव्यांगों के लिए, हमने शुरु किया है:

- ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करते समय, छूट का लाभ उठाने के लिए एकबारगी रजिस्ट्रेशन।
- व्हील चेअर की ऑनलाइन बुकिंग।
- सभी नए सवारी डिब्बे ब्रेल एनेबल्ड।

42. हमारे वरिष्ठ नागरिकों, और महिला यात्रियों के लिए:

- निचली शायिकाओं का कोटा बढ़ाया है। आगामी वित्त वर्ष में, हम प्रत्येक सवारी डिब्बे में वरिष्ठ नागरिक कोटे को 50% बढ़ा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ नगारिकों के लिए लगभग 120 निचली शायिकाएं प्रति रेलगाड़ी उपलब्ध होंगी।
- अधिक एस्क्लेटर और लिफ्ट उपलब्ध कराई हैं।
- महिला सुरक्षा के लिए सवारी डिब्बों में मध्यम भाग को आरक्षित किया गया है।

वाई-फाई

43. हमने रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर अपने युवा और कारोबारी यात्रियों के लिए, वाई-फाई सेवाएं शुरु की हैं। यह प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। इस साल 100 स्टेशनों पर और अगले 2 साल में 400 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। हम इस प्रयास में गूगल के साथ साझेदारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अन्य सभी सेवा प्रदाताओं और उद्यमियों को इस पहल में हमारे साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

रेलवे स्टेशन

44. यात्री का अनुभव मुख्य तौर पर एक रेलवे स्टेशन पर सेवाओं की कुशलता और गुणवत्ता पर निर्भर होता है। एक पुनः विकसित रेलवे स्टेशन, सेवा में सुधार लाने के अलावा, अधिक गैर-टैरिफ राजस्वों का सृजन करने का भी अवसर उपलब्ध कराएगा। हम विभिन्न मॉडल प्रयोग करते हुए अपने स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। इनमें से एक मॉडल के आधार पर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए वित्तीय बोली प्राप्त हो गई है जबकि अन्य 4 स्टेशनों बोली प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

45. हाल ही में, मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 400 रेलवे स्टेशनों का सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत पुनर्विकास किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इससे दुनिया में सबसे विशाल पारवहन अभिमुख विकास होने की आशा है, और इसलिए इसमें जटिल निर्णय लेने पड़ते हैं। अगले वित्त वर्ष के दौरान, निजी भागीदारी के लिए बैंक को स्वीकार्य सरंचना के आधार पर कुछ बड़े और मझौले स्टेशनों के लिए बोली प्रक्रिया शुरु किए जाने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शुरुआत करने के अलावा, हम

कतिपय अन्य रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए बहुपक्षीय वित्तीय निवेश लेने की संभावना भी तलाश रहे हैं और राज्य सरकारों से साझेदारी कर रहे हैं।

46. हम स्वच्छता का रचनात्मकता के साथ संगम करने का अनूठा प्रयास कर रहे हैं। मैंने अनेक सामाजिक संगठनों से हमारे स्टेशनों को सुंदर बनाने की अपील की थी। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बहुत से रेलवे स्टेशनों की दीवारों को भित्तिचित्रों में बदला गया है जिससे न केवल सौंदर्य में सुधार आया है बल्कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों के बारे में जागरुकता का प्रसार भी हुआ है। ऐसा ही एक विषय, जो विशेष उल्लेख का हकदार है, वन्य जीवन का संरक्षण है जिसका सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर चित्रों के माध्यम से सचित्र वर्णन किया गया है। हजारीबाग, बोरीवली, खार, उदयपुर, बीकानेर कुछ अन्य रेलवे स्टेशन हैं जो स्थानीय कला और प्रतिभा को दिखाते हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और अगले साल भी हमारे रेलवे स्टेशनों को ऐसा सौंदर्यपरक सहयोग जारी रखने का अनुरोध करता हूँ। हम आदिवासी कला को प्रदर्शित करने का विशेष प्रयास करेंगे।

सुरक्षा

47. अपने यात्रियों, खासतौर पर महिला यात्रियों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, निम्नलिखित प्रमुख पहलकदमियां की गई हैं:-

- अखिल भारतीय, 24/7 हेल्पलाइन नंबर 182
- 311 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी चौकसी की व्यवस्था की गई है। सभी बड़े रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी चौकसी के अंतर्गत लाया जाएगा।

संरक्षा

48. एक दुर्घटना या एक जीवन की हानि से मुझे अत्यंत दुख और पीड़ा होती है। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि हमें शून्य दुर्घटना व्यवस्था का अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए अभी-भी लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत कम दुर्घटनाओं के साथ हमारा संरक्षा रिकॉर्ड बेहतर रहा, फिर भी यहां बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है जो करने की जरूरत है। मेरा पक्का विश्वास है कि भारतीय रेल से दुर्घटनाओं का उन्मूलन करने के लिए आगे का मार्ग नवीनतम तकनीक को अपनाए

और आत्मसात किए जाने पर निर्भर है। हमने दुनिया के प्रमुख रेल संस्थानों, रेलवे टेक्नीकल रिसर्च इंस्टीटियूट, जापान और कोरियन रेल रिसर्च इंस्टीटियूट के साथ अनुसंधान एवं विकास साझेदारी प्रारंभ की है। वे मौजूदा नेटवर्क पर कामकाज में सुधार लाने के लिए कार्य करेंगे और इस प्रकार भारत में 'शून्य दुर्घटना' रेलवे प्रणाली के लिए रोडमैप उपलब्ध होगा। इसी दौरान, हमने डॉ. काकोडकर की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों की जांच की है और उनके क्रियान्वयन पर कार्य कर रहे हैं। हम अत्यधिक भीड़ वाली रेलगाड़ियों के लिए, मुख्य तौर पर उपनगरीय खंडों पर गाड़ी से गिरने से रोकने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2015-16 में हमने 350 चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंग बंद किए हैं और 1000 बिना चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंग समाप्त किए हैं। वर्तमान वर्ष में 820 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज को पूरा किया गया है और 1350 पर कार्य प्रगति पर है।

अन्य प्रमुख उपलब्धियां

ऊर्जा

49. पिछले साल मैंने अपने बजट भाषण में उत्तरोत्तर 3,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत करने का उल्लेख किया था, जिसे तीसरे वर्ष तक प्राप्त किया जाना था। यह कुल कर्षण सप्लाई लागत का लगभग 30% है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम अगले वित्त वर्ष में ही अर्थात निर्धारित समय से एक वर्ष पहले यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। भारतीय रेल ने पहली बार डीम्ड वितरण लाइसेंसी के ओहदे का इस्तेमाल करते हुए बिजली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिस्पर्धी दरों पर सीधे बिजली की खरीद की है। पहले से हस्ताक्षरित और कार्यान्वित, बिजली खरीद करारों से 1,300 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी। बिजली प्राप्ति के लिए पहले से शुरू की गई कार्रवाईयों से आगामी वर्ष के दौरान 1,700 करोड़ रु. की वार्षिक बचत होगी, जिससे कुल बचत 3,000 करोड़ रु. हो जाएगी। इसके अलावा, मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा संबंधी किफ़ायती उपायों से 300 करोड़ रु. की बचत का लक्ष्य है।

50. अब भारतीय रेल द्वारा उच्च भार वहन क्षमता वाले रेलइंजनों का निर्माण किया जा रहा है। इन रेलइंजनों का उपयोग बिजली यानों के उन्मूलन को संभव बनाएगा, जिसके द्वारा उनके स्थान पर यात्री सवारी डिब्बे लगाए जा सकेंगे, जिससे रेलगाड़ियों की वहन क्षमता का

संवर्धन होगा और यात्रा समय, गाड़ी की आवाज़ और ईंधन की खपत में भारी कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप हमारे कार्बन फुटप्रिंट में भी भारी कमी आएगी। वर्तमान वर्ष में ऐसे चार रेल इंजनों का निर्माण किया गया है और 2016-17 में अन्य 39 रेलइंजनों का निर्माण किए जाने की आशा है।

रेल विश्वविद्यालय

51. किसी भी विश्व स्तरीय रेल प्रणाली में कुशल जनशक्ति बनाए रखने के लिए रेल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने विश्वविद्यालय के रूप में पूर्णत: विकसित करने के लिए वड़ोदरा स्थित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी को चुना है। अगले वित्त वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं।

डिजिटल इंडिया

52. भारतीय रेल एक संगठन के रूप में समृद्धि के पथ पर तब तक प्रगति नहीं कर सकती है जब तक यह पथ 'डिजिटली' सज्जित न हो। इस वर्ष ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) का एप्लीकेशन शुरु किया गया था। उसके साथ, रेलपथ निरीक्षण, निगरानी और अनुरक्षण के कार्यकलाप एक आईटी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, और एस.एम.एस. और ई-मेल के रूप में ऑटोमैटिक अलर्ट जारी हो रहे हैं। टीएमएस के इन्वेंटरी प्रबंधन मॉडयूल के परिणामस्वरूप इन्वेंटरी में 27,000 एमटी की कमी आई है, जिससे 64 करोड़ रु. की बचत हुई है और 53 करोड़ रु. मूल्य के समकक्ष 22,000 एमटी स्क्रैप की पहचान हुई है। 2016-17 के दौरान, संपूर्ण भारतीय रेल पर यह प्रणाली कार्यान्वित हो जाएगी।

53. भारतीय रेल ने अपने अधीन भूमि का रिकॉर्ड रखने हेतु केन्द्रीकृत भूमि डाटा का डिजिटलीकरण करने के लिए एक एप्लीकेशन विकसित की है।

आगे का मार्ग

54. चूँकि मैं नई पहलों का निरूपण करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे जरा एक कदम वापस जाने की अनुमति दीजिए। पिछले साल के बजट का एक प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और रेल यात्राओं को आनंदप्रद बनाना था। हम इस गति को बनाए रखेंगे और भारतीय रेल के नेटवर्क पर प्रतिवर्ष सवारी करने वाले 7 खरब यात्रियों में प्रत्येक की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कड़ा प्रयास करेंगे।

यात्रा को और आरामदायक बनाना

55. हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है जो सभी के, विशेषकर किसानों, कामगारों, विकलांग और गरीबों के लाभ के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सबका साथ, सबका विकास हमारे लिए बस एक नारा नहीं है, यह हमारे सभी विचारों और कार्यों में व्याप्त है। हमारा प्रत्येक ग्राहक हमारा ब्रांड अम्बेसडर है, साथ ही हमारे अस्तित्व का मूल कारण भी। इसलिए, प्रत्येक बार उसके यात्रा करने पर उसकी संतुष्टि की मात्रा बढ़नी चाहिए। हमारे प्रत्येक ग्राहक को प्रसन्न करने का अनुसरण करते हुए, मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

अनारक्षित यात्रियों के लिए – ***अंत्योदय एक्सप्रेस और दीन दयालु सवारी डिब्बे***

56. इस सरकार का पक्का विश्वास है कि भारत का भाग्य तब तक नहीं बदलेगा जब तक आम आदमी या महिला की जिंदगी में सुधार नहीं आएगा। न केवल वह हमारी नीति निर्धारण का केन्द्र बिंदु है बल्कि हमारे सार्वजनिक उद्घोषणा में और हमारी विचारधारा में सर्वत्र व्याप्त है। हम आम आदमी के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस, लंबी दूरी की पूर्णतया अनारक्षित सुपरफास्ट रेलगाड़ी सेवा चलाने का प्रस्ताव कर रहे हैं जो व्यस्ततम मार्गों पर चलाई जाएंगी।
57. हम आम जनमानस के लिए अपनी वहन क्षमता का सवंर्धन करने हेतु अनारक्षित यात्रा के लिए कुछ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में दो से चार दीन दयालु सवारी डिब्बे भी लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इन सवारी डिब्बों में पीने के पानी की सुविधा होगी और अधिक संख्या में मोबाइल चार्जिंग पाइंट दिए जाएंगे।

आरक्षित यात्रियों के लिए – ***हमसफ़र और तेजस और उदय***

58. मैं तीन चुनिंदा रेलगाड़ी सेवाओं की घोषणा कर रहा हूँ, हमसफ़र और तेजस और उदय। हमसफ़र और तेजस, किराया दरसूची और गैर-किराया दरसूची उपायों के माध्यम से लागत वसूली सुनिश्चित करेंगी। हमसफ़र पूर्णतया वातानुकूलित तृतीय एसी सेवा होगी, जिसमें भोजन की व्यवस्था वैकल्पिक होगी।

59. दूसरी ओर, तेजस भारत में रेलगाड़ी यात्रा के भविष्य को दिखाएगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे अधिक गति पर चालित, ये जवाबदेही और उन्नत ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित

करने के लिए एक सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनबोर्ड सेवाएं पेश करेगी जैसे मनोरंजन, स्थानीय भोजन, वाई-फाई आदि।

60. हम सबसे व्यस्त मार्गों पर रात्रिकालीन उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन्ड यात्री (उदय) सेवा भी शुरु करने का प्रस्ताव कर रहे हैं जो वहन क्षमता को लगभग 40% बढ़ाने की संभावना रखती हैं।

टिकटिंग

61. बुकिंग खिड़कियों पर यात्रियों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए, हम उपनगरीय और छोटी दूरी वाले यात्रियों के लाभ के लिए हैंड हैल्ड टर्मिनलों के जरिए टिकटों की बिक्री शुरू करना चाहते हैं। इससे हम न्यूनतम अवसंरचनात्मक आवश्यकता के अनेक बिक्री स्थल तैनात कर सकते हैं। हम टिकट वैंडिंग मशीनों के जरिए प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री भी शुरू करना चाहते हैं, जो नकद राशि के अलावा क्रेडिट/डेबिट कार्डों के साथ भी सक्षम होंगी।

62. हम आगामी 3 माह में विदेशी पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के लिए विदेशी डेबिट/क्रेडिट कार्डों से ई-टिकटिंग सुविधा शुरू करेंगे।

63. हमारे पत्रकार मित्रों के लिए, हम उन्हें रियायती पासों पर टिकटों की ई-बुकिंग की सुविधा देना चाहते हैं। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही है और उन्हें यह सुविधा मुहैया कराना मेरा सौभाग्य है।

64. पीआरएस टिकटों को रद्द कराने के लिए यात्री को निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिफंड के लिए बुकिंग खिड़की तक जाना पड़ता है। यात्रियों के लिए यह बहुत असुविधाजनक होता है। हम हेल्पलाइन 139 पर यात्रियों को पंजीकृत फोन नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करते हुए टिकट रद्द कराने की सुविधा शुरू करना चाहते हैं।

65. हम बिना टिकट यात्रा की समस्या से निपटने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर पायलट आधार पर बार कोड वाली टिकटें, स्कैनर और एक्सेस कंट्रोल शुरू करेंगे और यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेंगे।

66. हमने सुबह के घंटों के दौरान, तत्काल टिकटों की बिक्री शुरू होने के समय, सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। अभी-भी इसमें वैध यात्रियों को गाड़ी के टिकट न मिलने की शिकायतें आ रही हैं। इसलिए, तत्काल काउंटरों को उत्तरोतर ढंग से सीसीटीवी के दायरे में लाने की हमारी योजना है। पीआरएस वेबसाइट की सुरक्षा विशेषताओं के आवधिक रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट और प्रमाणन की व्यवस्था करने की हमारी योजना है।

विकल्प- मांग पर गाड़ी

67. अक्तूबर 2015 में शुरू की गई विकल्प (वैकल्पिक गाड़ी एकोमोडेशन प्रणाली) योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि प्रतीक्षा सूची के यात्री विनिर्दिष्ट गाड़ियों में एकोमोडेट किए जाने के लिए अपनी इच्छा दर्ज करा सकें।

स्वच्छता

68. 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' के अभियान को और आगे बढ़ाते हुए, हम स्टेशनों और गाड़ियों में साफ-सफाई में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय शुरू करना चाहते हैं:

i. अखिल भारतीय स्तर पर क्लीन माई कोच सेवा शुरू करना, जिसमें यात्री एसएमएस के जरिए अपने कोच/शौचालय को साफ करने का अनुरोध कर सकते हैं।

ii. नियमित अंतराल पर तीसरी पार्टी ऑडिट और यात्रियों से फीडबैक के आधार पर ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों का रैंक निर्धारण करना।

iii. ए1 श्रेणी के प्रत्येक स्टेशनों पर चरणबद्ध आधार पर वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइक्लिंग सेंटर की स्थापना करना; अगले वित्त वर्ष में 5 सेंटर खोले जाएंगे।

iv. चुनिंदा स्टेशनों, पहुंच मार्गों और निकटवर्ती कालोनियों में साफ-सफाई में सुधार लाने के लिए 'जागरूकता अभियान' चलाना।

v. अगले वित्त वर्ष में 30,000 अतिरिक्त जैव-शौचालय लगाना।

vi. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिला यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए, चुनिंदा स्टेशनों के सभी प्लेटफार्मों पर पोर्टेबल जैव-शौचालय मुहैया कराना। शौचालय बनाने और

उनके रखरखाव के लिए अन्य नवीन उपायों को भी शुरू करने की मेरी योजना है, जैसे विज्ञापन अधिकार, सीएसआर स्पांसरशिप, सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक सहायता आदि।

स्टेशनों पर खानपान और स्टॉल

69. ग्राहकों की संतुष्टि के लिए खानपान एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे ग्राहकों को गुणवत्तापरक भोजन मुहैया कराने के हमारे उद्देश्य के अनुसरण में, खानपान सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है:

i. आईआरसीटीसी खानपान सेवाओं को चरणबद्ध आधार पर शुरू करेगी। आईआरसीटीसी भोजन तैयार करने और भोजन वितरित करने में खानपान सेवाओं में सुधार करेगी।

ii. ई-खानपान सेवाओं को 45 बड़े स्टेशनों से बढ़ाकर ए-1 श्रेणी और ए श्रेणी के सभी 408 स्टेशनों पर यह सुविधा मुहैया कराना।

iii. गाड़ियों में वैकल्पिक खानपान सेवाएं शुरू करने के लिए संभावनाओं का पता लगाना। इनमें यात्रियों के लिए स्थानीय व्यंजन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

iv. गाड़ियों में ताजा और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा परिचालित, मशीनीकृत और उन्नत 10 अन्य बेस किचन स्थापित करना।

v. खानपान सेवाओं की गुणवत्ता का वांछित स्तर सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट करना।

vi. मौजूदा एकल उद्देश्य स्टॉलों के स्थान पर बहु-उद्देशीय स्टालों की नई नीति शुरू करना, जिसमें यात्रियों को प्रत्येक स्टॉल पर दुग्ध उत्पादों और ओटीसी दवाइयों सहित अनेक सेवाएं मिल सकें।

vii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग आदि को खानपान इकाइयों में आरक्षण लागू करना। हम प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में महिलाओं के

लिए 33% का उप-कोटा भी शुरू करेंगे। इसके अलावा, स्थानीय स्वामित्व और सशक्तिकरण के लिए, जिला निवासियों को स्टेशनों पर वाणिज्यिक लाइसेंस देने में प्राथमिकता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

viii. हमारे ग्राहकों को कुल्हड़ में चाय पीने के विकल्प की व्यवहार्यता का पता लगाना।

ठहराव

70. भारतीय रेल ने परिचालनिक और वाणिज्यिक हॉल्ट के बीच ऐतिहासिक रूप से अपनी पहचान बनाई है। यात्रियों की सुविधा के लिए, मैं सभी परिचालनिक हॉल्ट स्टेशनों को वाणिज्यिक हॉल्ट में बदलने का प्रस्ताव रखता हूँ। इससे उन यात्रियों को लाभ मिलेगा जो इन हाल्ट से गाड़ी में नहीं चढ़ सके अथवा गाड़ी से उतर गए।

रेल मित्र सेवा

71. हमने स्टेशनों पर वृद्धों और दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए कोंकण रेलवे में सारथी सेवा शुरू की है। हम बहुत से और स्टेशनों पर इस सेवा का विस्तार करेंगे। हम अपने यात्रियों के लिए मौजूदा सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे, जिसमें यात्री, मौजूदा पिक अप एंड ड्राप सेवा और व्हील चेयर सेवाओं के अलावा भुगतान आधार पर बैटरी चालित कारें, कुली सेवाएं आदि बुक कर सकते हैं।

दिव्यांगों के लिए उपाय

72. सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्य के अनुसरण करते हुए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पुन: विकसित किए जा रहे सभी स्टेशनों का दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। आगामी वित्त वर्ष के दौरान हम ए1 श्रेणी स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफार्म पर दिव्यांगों के लिए कम-से-कम एक शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इन स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में व्हील चेअरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।

यात्रियों के लिए यात्रा बीमा

73. हम यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तथापि, अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। इन घटनाओं से यात्रियों को होने वाले वित्तीय नुकसान को

कम करने के लिए, हम बीमा कंपनियों से रेल यात्राओं के लिए बुकिंग करते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।

विश्रामालयों की घंटे के आधार पर बुकिंग,

74. हमारे रेल नेटवर्क पर यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रसन्नता होगी यदि उन्हें दिन भर के लिए अपने कारोबार के सिलसिले में जाने से पहले तैयार होने के लिए स्टेशन परिसर में ही कोई स्थान मिल जाए। हम यात्रियों की इस जरूरत को पूरा करने के लिए विश्रामालयों की बुकिंग मौजूदा न्यूनतम 12 घंटे के स्थान पर घंटे के आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। इसके अलावा, हम विश्रामालयों को आईआरसीटीसी को सौंप देंगे जो इनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

जननी सेवा

75. हम शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं की कठिनाइयों को कम करना चाहते हैं और इस प्रयोजन हेतु, गाड़ियों में बच्चों के लिए खानपान के पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशनों पर शिशु आहार, गरम दूध और गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा और गाड़ियों के शौचालयों में शिशुओं के लिए चेंजिंग बोर्ड भी मुहैया कराए जाएंगे।

स्मार्ट सवारी डिब्बे

76. यात्रियों के आराम में वृद्धि करने की दृष्टि से, हम सवारी डिब्बों के डिजाइन और लेआउट में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं ताकि वहन क्षमता को बढ़ाया जा सके और आटोमेटिक दरवाजे, बार-कोड रीडर, बायो वैक्यूम टॉयलेट, वॉटर लेवल इंडिकेटर, कूड़ेदान की व्यवस्था, एर्गोनोमिक सीटें, बेहतर साज-सज्जा, वेंडिंग मशीनें, मनोरंजन स्क्रीन, विज्ञापन के लिए एलईडी लिट बोर्ड, पी ए सिस्टम और अन्य सुविधाओं सहित नई सुख-सुविधाओं की व्यवस्था हो। इन नए स्मार्ट (स्पेशली मॉडिफाइड इस्थेटिक रीफ्रेशिंग ट्रेवल) सवारी डिब्बों से हमारे ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और उच्चतर वहन क्षमता के कारण परिचालन की यूनिट लागत की कमी भी सुनिश्चित होगी।

मोबाइल ऐप

77. इस समय, हमारे पास टिकटिंग, शिकायत निवारण और अन्य समस्याओं के लिए अलग-अलग डिजिटल समाधान हैं। ये सभी सुविधाएं दो मोबाइल ऐप में एकीकृत कराने की हमारी मंशा हैं : एक में टिकट संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे और दूसरे में हमारी सभी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण का प्रावधान होगा और सुझाव प्राप्त किए जाएंगे।

ग्राहक इंटर फेस में सुधार लाना

78. भारतीय रेल का सतत् प्रयास रहता है कि अपने सभी क्रियाकलापों में ऐसी नई पहल की जाएं जिससे ग्राहक की आवश्कताओं को पूरा करना सुनिश्चित हो। इसके लिए हम ग्राहकों से सीधे संपर्क में आने वाले रेल कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों, जिन्हें हम सेवा प्रदाताओं के जरिए नियुक्त करते हैं, को कार्य-कुशल बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा, ग्राहकों के संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों की वर्दी में बदलाव किए जाएंगे ताकि हमारे नेटवर्क पर उन्हें अलग से पहचाना जा सके।

79. हम गाडियों में सूचना बोर्ड लगाएंगे जिनमें गाड़ियों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का उल्लेख होगा और यात्रियों को आने वाले स्टेशनों के बारे में रियल टाइम सूचना प्रदान करने के लिए सवारी डिब्बों के भीतर जीपीएस आधारित डिजिटल डिस्पले बोर्ड भी लागए जाएंगे। ये सेवाएं प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से मुहैया कराई जाएंगी।

80. 2000 स्टेशनों पर रेल डिस्पले नेटवर्क नामक 20,000 स्क्रीन वाले एक हाई-टेक केन्द्रीकृत नेटवर्क स्थापित करने का कार्य जारी है। इससे यात्रियों को रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी और बड़े पैमाने पर विज्ञापन की पर्याप्त संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

81. हम बेहतर यात्री सुविधाएं, सतर्क एवं संवेदनशील ग्राहक सेवा, त्वरित शिकायत निवारण और बेहतर वाणिज्यिक सोच सुनिश्चित करके स्टेशनों पर रेल संगठन को सुदृढ़ करना चाहते हैं। ए1 श्रेणी के सभी स्टेशनों पर यथोचित शक्तिसंपन्न स्टेशन निदेशक तैनात किए जाएंगे जिनकी सहायता के लिए विभिन्न कोटि के कर्मचारियों का एक कार्यदल भी होगा जो स्टेशनों को ग्राहक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में चलाने का कार्य करेंगे। हम गाड़ी में इन सभी सुविधाओं के लिए एक व्यक्ति को जवाबदेह बनाएंगे।

82. भारत में तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भारतीय यात्रियों में एक बड़ा स्वाभविक आकर्षण रहता है। हमारी मंशा अजमेर, अमृतसर, बिहार शरीफ़, चेंगनूर, द्वारका, गया, हरिद्वार, मथुरा, नागपट्टनम, नांदेड़, नासिक, पाली, पारसनाथ, पुरी, तिरूपति, वेलंकन्नी, वाराणसी और वास्को जैसे धार्मिक महत्व के स्टेशनों के सौंदर्यीकरण तथा यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने का का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की है। हम महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए आस्था सर्किट गाड़ियां भी चलाना चाहते हैं।

सैटलाइट टर्मिनल

83. पिछले वर्ष मैंने कुछ स्टेशनों पर सैटलाइट टर्मिनल विकसित किए जाने के बारे में घोषणा की थी। इसी कार्य को अगले अनेक स्तरों तक बढ़ाते हुए, मैं सभी राज्यों से अपील करता हूँ कि वे आगे आएं और पीपीपी माध्यम से सैटलाइट टर्मिनल स्थापित करने में भागीदारी करें। फिलहाल, आउटर सिगनलों पर होने वाले विलम्ब को कम करने और रेक टर्नअराउड में सुधार लाने के लिए अल्पकालीन उपायों की पहचान करने के लिए पायलट आधार पर विस्तृत परिचालनिक शोध कराने की हमारी योजना है।

पोर्टर, हमारे सहायक

84. पोर्टर्स हमारी यात्रा को आरामदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेल की छवि बदलने के लिए उन्हें नई वर्दी देने और सॉफ्ट स्किल में उन्हें प्रशिक्षित करने की हमारी मंशा है और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ साथ यात्रियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की अपनी परंपरा को भी कायम रखना चाहते हैं। हम उन्हें सामूहिक बीमा सुविधा देने की पद्धतियों का भी पता लगाएंगे। अब से, हम उनको सहायक के नाम से पुकारने में खुशी महसूस करेंगे।

हाई स्पीड रेल

85. जापान सरकार की सहायता से अहमदाबाद से मुम्बई तक एक हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर का कार्य किया जा रहा है। हाई स्पीड परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना इस माह में पंजीकृत की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य लाभ

भारतीय रेल को उन्नत प्रौद्योगिकी और नवीन विनिर्माण क्षमता मुहैया कराना होगा, जिसका मौजूदा नेटवर्क के अन्य क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

मनोरंजन

86. हम गाड़ियों में पीए सिस्टम संस्थापित कर के गाड़ियों में मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए एफएम रेडियो स्टेशनों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव करते हैं।

87. इस समय शताब्दी, राजधानी और दूरांतो गाड़ियों में भारतीय रेल की द्विभाषिक ऑनबोर्ड मैगज़ीन 'रेल बंधु' यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती है। इसे सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी आरक्षित श्रेणियों के यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा। हम 'रेल बंधु' को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित करना शुरू करेंगे।

यात्री यातायात – उपनगरीय यातायात

88. मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी है और इसके लिए एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है। बहरहाल, उपनगरीय रेल प्रणाली, जो शहर की जीवन रेखा है, उस पर अत्यधिक दबाव है। आगे की कार्रवाई के लिए एमयूटीपी–III के लिए नीति आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। हम इसे वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले प्राप्त करने और चर्चगेट–विरार और सीएसटीएम-पनवेल खंडों के बीच दो ऐलीवेटिड उपनगरीय कॉरिडोरों के बीच शीघ्र निविदा देने का कार्य शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रीमियम कॉरिडोर को मैट्रो लाइनों से जोड़ा जाएगा, जिनकी योजना राज्य सरकार द्वारा मौजूदा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रस्तावित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। हम आगामी वित्त वर्ष में मुम्बई उपनगरीय स्टेशनों के निचली सतह के सभी प्लेटफार्मों की सतह को ऊँचा करना चाहते हैं ताकि इस वजह से यात्रियों की संरक्षा को होने वाले खतरे को दूर किया जा सके।

89. कोलकाता में, हम लगभग 100 किमी. पर मेट्रो के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। जब यह कार्य पूरा हो जाएगा तब मौजूदा क्षमता चार गुनी हो जाएगी। मैंने कोलकाता मेट्रो के ईस्ट- वैस्ट कॉरिडोर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर लिया है और मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस परियोजना के चरण-I का कार्य जून, 2018 में पूरा कर लिया जाएगा। हम पूर्वी-पश्चिमी कॉरिडोर को 5 कि.मी. तक और बढ़ाने की संभावनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

90. हमारी राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली पर प्रदूषण का स्तर बढ़ने से अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और इसमें 21 स्टेशनों वाली रिंग रेलवे प्रणाली को पुनः चालू कराने से राहत पंहुचाई जा सकती है। हम इस अवसंरचना को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के साथ भागीदारी करेंगे।

91. हमारा प्रस्ताव है कि एक नया निवेश ढांचा तैयार करके भारतीय रेल की एक एकीकृत उपनगरीय पर्यावरण हितैषी प्रणाली बनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए। भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ इक्विटी अंशदान करेगी और परिचालन पर लागत की तटस्थता सुनिश्चित की जाएगी। हम अगले 4 महीनों में इस संबंध में एक विस्तृत नीति तैयार करेंगे। हम नवीन वित्तीय तंत्र की व्यवस्था करके अहमदाबाद, हैदराबाद और चेन्नै उपनगरीय खंडों के विकास के लिए क्रमशः गुजरात, तेलगांना और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करना चाहते हैं।

92. देश के प्रौद्योगिकी के केंद्र, बेंगलुरू के लिए एक व्यापक उपनगरीय प्रणाली की आवश्यकता है। हम इस प्रयास में राज्य सरकार के साथ भागीदारी करेंगे।

93. तिरूवनंतपुरम, जो ईश्वर के अपने देश केरल की राजधानी है, के लिए भी इसी तरह की संरचनाओं और वित्तीय तंत्रों का सृजन किया जाएगा।

94. मैं मुंबई उपनगरीय गाड़ियों में व्यस्त समय के दौरान भीड़-भाड़ को कम करने के लिए राज्य सरकार से कार्यालय के काम के घंटों के लिए अलग-अलग समय रखने की अपील करता हूँ।

परिवहन में भारतीय रेल के हिस्से को पुनः प्राप्त करना

माल-यातायात

95. परिवहन में भारतीय रेल के हिस्से में काफी समय से लगातार गिरावट आ रही है। इस गिरावट का न केवल रेलवे बल्कि समूची अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम इस परिस्थिति को बदलने का निश्चय करते हैं। इस समस्या के तीन समाधान हैं – भारतीय रेल के द्वारा लदान की जा रही सामग्रियों को बढ़ाना, दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना और टर्मिनल क्षमता का निर्माण करना।

फ्रेट बास्केट का विस्तार

96. भारतीय रेल के माल यातायात में 10 थोक पण्यों की प्रधानता है जिनका शेयर लगभग 88% है। अपने राजस्व आधार का विस्तार करने के लिए हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। एक परिपूर्ण मार्केट का अध्ययन किया जा रहा है और विस्तृत मांग एवं आपूर्ति परिदृश्य, सेवा स्तर और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा ताकि या तो कंटेनरीकरण के जरिए इस यातायात को वापस प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी या इसके लिए नए डिलिवरी मॉडल अर्थात रोल ऑन रोल ऑफ आदि को विकसित किया जाएगा और कार्यान्वयन किया जाएगा।

97. नेटवर्क क्षमता की सीमाओं के कारण फिलहाल हम समय-सारणीबद्ध मालगाड़ियां नहीं चला पा रहे लेकिन इस वर्ष से हम पायलट आधार पर समय-सारणीबद्ध फ्रेट–कंटेनर, पार्सल और विशेष पण्यों के लिए गाड़ियां चलाना शुरू करेंगे।

कंटेनर यातायात

98. कोयला और विनिर्दिष्ट खनिज अयस्कों को छोड़कर प्रत्येक किस्म के यातायात के लिए कंटेनर सेक्टर खोल दिया जाएगा और गैर-व्यस्त अवधि के दौरान हम आंशिक रूप से भरी हुए गाड़ियां चलाने की अनुमति भी देंगे। सभी मौजूदा टर्मिनलों/शेडों, जहां-कहीं व्यावहारिक पाया जाए, को कंटेनर यातायात की अनुमति प्रदान की जाएगी।

टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना

99. भारतीय रेल की मौजूदा भाड़ा संरचना से माल यातायात बाजार में अन्य सेवाओं के मुकाबले हमारी सेवाएं महंगी हो गई हैं। यातायात के अन्य साधनों की तुलना में एक प्रतिस्पर्धी भाड़ा संरचना तैयार करने, मल्टी-पाइंट लदान/उतराई और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न भाड़ा दरें लागू करने के लिए टैरिफ नीति की समीक्षा की जाएगी। पूर्व निर्धारित कीमत वृद्धि सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपने महत्वपूर्ण माल यातायात ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक टैरिफ करारों पर हस्ताक्षर करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिससे भारतीय रेल की आमदनी और हमारे ग्राहकों की लागत का पूर्वानुमान लगाया जा सके।

टर्मिनल क्षमता का निर्माण

100. वेयरहाउसों और परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता भी एक कारण है जिसकी वजह से संभावित ग्राहक रेलवे से दूर चले जाते हैं। परिवहन की श्रृंखला को पूरा करने के लिए,

रेल साइड लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस बनाने का प्रस्ताव है। इन लॉजिस्टिक पार्कों और वेयरहाउसों का निर्माण पीपीपी माध्यम किया जाएगा, जिससे अपेक्षित कुशलता आएगी और निवेश प्राप्त होगा साथ ही रेलवे की ओर ज्यादा यातायात आकर्षित करने में भी इससे मदद मिलेगी। ट्रांसलोक, भारत की परिवहन लॉजिस्टिक कंपनी बन जाने के बाद, राष्ट्रीय परिवहन प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका में हम आधारभूत परिवर्तन पाएंगे। हमारा ध्यान माल यातायात कारोबार के लिए लास्ट माइल कनेक्विविटी मुहैया कराने और लॉजिस्टिक लागतों में भारी कमी करने पर होगा। 2016-17 में ट्रांसलोक द्वारा कम से कम 10 माल शेड विकसित किए जाएंगे। ऑटोमोबाइल यातायात को आकर्षित करने के लिए, हम शीघ्र ही चेन्नै में भारत के पहले रेल ऑटो हब का उद्घाटन करेंगे।

101. रेल साइड वेयरहाउसों पर जोर दिए जाने से माल यातायात टर्मिनलों के निकट खाली भूमि पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किसानों और मछुआरों को इस सुविधा का इस्तेमाल करने में प्राथमिकता दी जाएगी। अगले 3 माह में इस संबंध में एक नीति जारी की जाएगी।

ग्राहकों का परिपोषण

102. अपने प्रमुख माल हितधारियों के साथ संपर्क करने के लिए हम प्रमुख ग्राहक प्रबंधक नियुक्त करेंगे। सभी प्रकार के पत्राचार और शिकायतों के निपटान के लिए इन प्रमुख ग्राहक प्रबंधकों के साथ एक ही स्थान पर संपर्क किया जा सकेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे ग्राहक प्रतिबद्ध चार्टर विकसित करेगी, जिसमें यात्रियों और फ्रेट ग्राहकों के लिए भारतीय रेल की सेवा स्तर की प्रतिबद्धताओं का उल्लेख होगा।
103. हम सामान्य प्रयोजन के माल डिब्बों को पट्टे पर देने की व्यवहार्यता की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

किराए से इतर राजस्व

104. यद्यपि भारतीय रेल के साथ वास्ता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तथापि हम किराए से इतर स्रोतों के जरिए 5% से भी कम राजस्व अर्जित करते हैं। विश्व की बहुत सी रेल प्रणालियां किराए से इतर स्रोतों से 10% से 20% राजस्व अर्जित करती हैं। अगले

5 वर्ष की अवधि में, हम परिसंपतियों का मौद्रीकरण करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्यों से इस विश्व औसत को हासिल करने का प्रयास करेंगे। हमने इसके लिए प्रयास पहले ही शुरू कर दिए हैं।

(क) स्टेशन पुनर्विकास: स्टेशनों के पुनर्विकास का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। इससे खाली भूमि और स्टेशन इमारतों के ऊपर के स्थान के अधिकारों के वाणिज्यिक उपयोग के जरिए अपनी भूमि और इमारतों के मौद्रीकरण में सहायता मिलेगी।

(ख) *रेलपथ के आस-पास की भूमि का मौद्रीकरण*: भारतीय रेलवे के पास अपने रेल नेटवर्क के आस-पास अत्यधिक भूमि उपलब्ध है। बागवानी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हम इस स्थान को पट्टे पर देंगे। इससे वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, भोजन सुरक्षा में सुधार होगा। रेलवे भूमि पर अतिक्रमणों की भी रोकथाम होगी। इस ट्रैक का इस्तेमाल करके सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना की भी जांच की जाएगी।

(ग) *सॉफ्ट परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण*: भारतीय रेलवे यात्री की प्राथमिकता, टिकटिंग के पैटर्न, पण्य प्रवाह, गाड़ी चालन तथा अन्य विभिन्न सेवाओं तथा परिचालनों से संबंधित सूचना का डाटा संकलित करती है। हम अपने डाटा, सॉफ्टवेयर और भारतीय रेलवे द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं जैसे कि पीएनआर इन्क्वायरी का मौद्रीकरण कर सकते हैं, इनका अन्य भागीदारों द्वारा वाणिज्यिक दृष्टि से लाभ उठाया जा रहा है परंतु साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्राहकों की निजता का ख्याल रखा जाए। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के बड़ी संख्या में इस्मेमाल को ध्यान में रखते हुए इस साइट पर भी ई-कामर्स गतिविधियों का लाभ प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं।

(घ) *विज्ञापन*: भारतीय रेलवे के पास विशाल भौतिक और प्राकृतिक अवसंरचना है, जिसका विज्ञापन के माध्यम से वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है। हम अपने स्टेशनों, गाड़ियों और बड़े स्टेशनों के रेलपथ के आस-पास की भूमि पर विज्ञापन संबंधी संभावनाओं का इस्तेमाल करने पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। राजस्व अर्जित करने के लिए हम ग्राहकों के सीधे संपर्क में आने वाले संसाधनों का विज्ञापन के लिए

इस्तेमाल करने के लिए वर्दी आदि सहित कई मदों की को-ब्रांडिंग के लिए एजेंसियों के साथ भागीदारी करने का प्रयास करेंगे। हम अगले 3 महीने में कम-से-कम 20 स्टेशनों पर राजस्व अर्जन संबंधी संभावनाओं का पता लगाने के लिए मॉडल तैयार करेंगे। हमारा लक्ष्य विज्ञापन राजस्व को कुल मिलाकर मौजूदा राजस्व का 4 गुना करना है।

(ङ) पार्सल व्यवसाय को ओवरहॉल करना: हमारी योजना राष्ट्रीय सीईपी (कोरियर, एक्सप्रेस और पार्सल) बाजार में रेलवे के हिस्से में भारी वृद्धि करने के लिए, मौजूदा पार्सल नीतियों को उदार बनाने की है, जिसमें इस सेक्टर को कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए खोला जाना शामिल है। इस मार्केट सेगमेंट के लिए द्वार से द्वार तक संपर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और हम अपनी सेवाओं की पेशकश के दायरे को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, खास तौर पर ई-कामर्स जैसे उदीयमान क्षेत्र में। हम पार्सल की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक पायलट परियोजना भी शुरू करेंगे।

(च) *विनिर्माण कार्यकलापों से राजस्व*: घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अर्थपूर्ण भागीदार बनने के लिए उत्पादन यूनिटों तथा वर्कशापों में उत्पादन बढ़ाकर और बेहतर विनिर्माण पद्धतियों को अपनाकर रेलों के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध कराई जा सकती है। हम इन यूनिटों को आवश्यक शक्तियां और प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे ताकि निर्यात तथा घरेलू सप्लाई के माध्यम से 2020 तक लगभग 4,000 करोड़ रुपए तक वार्षिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

प्रक्रिया में सुधार

ईपीसी परियोजना

105. भारतीय रेल परियोजनाओं में बड़े व्यावसायिक भागीदारों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने और लागत तथा समय में वृद्धि को न्यूनतम करने के लिए मैंने पिछले वर्ष ईपीसी आधारित ठेकेदारी को अपनाने के संबंध में घोषणा की थी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने ईपीसी माध्यम से निर्माण कार्य शुरू करने के लिए मानक दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया है और 2016-17 में इसके जरिए कम से कम 20

परियोजनाएं कार्यान्वित करेंगे, हम 300 करोड़ रु. की लागत वाले सभी निर्माण कार्यों को ईपीसी ठेकों के जरिए प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

कार्य निष्पादन आऊटपुट पैरामीटर आधारित ठेका

106. कार्य निष्पादन आऊटपुट पैरामीटर आधारित ठेका: भारतीय रेल ने सफाई, सुविधा प्रबंधन आदि जैसे आऊट-सॉर्सिंग ठेकों के जरिए गैर- परिचालनिक क्षेत्रों में निजी पार्टियों की सेवाएं लेती हैं। हम इन ठेकों की सेवाओं की समीक्षा करना चाहते हैं ताकि इन्हें एकीकृत किया जा सके और इन्हें आसान बनाने और इनके परिणाम पर ध्यान दिया जा सके। यह हमारी ठेका व्यवस्था और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने की ओर एक आधारभूत कदम होगा।

परियोजना प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

107. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुसार, हम परियोजना प्रबंधन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकीय समाधानों का सहारा लेंगे। हम सभी बड़ी परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की कहीं से भी समीक्षा करने के लिए नवीनतम ड्रोन और जियो स्पैटियल आधारित सैटलाइट प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहते हैं। अगले वित्त वर्ष में, समर्पित माल यातायात गलियारे की प्रगति की निगरानी करने के लिए इसे चालू किया जाएगा।

समूची प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकरण

108. आईटी के क्षेत्र में हमारी नीतियां टुकड़ों में संचालित रही हैं, हमने समूची प्रणाली का एकीकरण शुरू किया है जो क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार से नवरचना में भागीदारी के मॉडल के माध्यम से चलाए जाने वाले उद्यम संसाधन प्रणाली के समान है। इसके लिए एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है।

रेल विकास प्राधिकरण- एक बड़ा कदम

109. सेवाओं की उचित कीमत निर्धारण, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, ग्राहकों के हितों के संरक्षण और कार्यकुशलता के मानकों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र विनियमन तंत्र अनिवार्य है। अतः मैंने पिछले वर्ष रेल विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की थी। हमें आशा है कि हितधारियों से विस्तृत परामर्श के पश्चात् ड्राफ्ट बिल तैयार कर लेंगे। पारदर्शी और सरल

चयन प्रक्रिया के जरिए इस संस्थान की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी और रेल मंत्रालय द्वारा इस पर निगरानी रखी जाएगी। मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास हमारे सारे हितधारियों का मनोबल ऊंचा करने में सहायक होगा।

नवारंभ- एक नई शुरूआत

नवीनीकरण- संरचनागत बदलाव

110. संगठनात्मक पुनर्संरचना : भारतीय रेल में विभिन्न कार्यात्मक अंगों में समन्वय का अभाव और व्यावसायिक सोच की कमी के कारण उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सका, जिन्हें हासिल करने में यह सक्षम है। एक कॉमन कॉरपोरेट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस संगठन की कार्यप्रणाली को पुनः निर्धारित करना ही एकमात्र समाधान है। इस प्रयोजन के लिए मैं रेलवे बोर्ड का व्यावसायिक तरीके से पुनर्गठन करने और इस संगठन का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को समुचित शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। शुरुआत में किराए से इतर राजस्व, गति बढ़ाने, चालन शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए रेलवे बोर्ड के भीतर क्रॉस फंक्शनल निदेशालयों की स्थापना की जाएगी। अधिकारियों की नई भर्ती के लिए हम संवर्गों के एकीकरण की संभावना का पता लगाएंगे। भारतीय रेल के साथ कारोबार को सफल बनाने के लिए हम पीपीपी सेल को भी मजबूत बनाएंगे।

सशक्तिकरण-हमारी योजना पद्धतियों में सुधार करना

111. *रेलवे योजना एवं निवेश संगठन* **:** विद्यमान अवसंरचना को विकसित करने और उसे अधिक मजबूत बनाने के लिए यह अत्यधिक उपयुक्त है कि उनके लिए निवेश की व्यवस्था अत्यधिक प्रभावशाली और पारदर्शी ढंग से की जाए। ऐसा करने के लिए हमारी मंशा रेल योजना एवं निवेश संगठन स्थापित करने की है। इस संगठन का कार्य हमारी मध्यावधि (5 वर्ष) तथा दीर्घावधि (10 वर्ष) की कोरपोरेट योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना और उसके आधार पर उन परियोजनाओं की पहचान करना है जो कोरपोरेट लक्ष्यों

को पूरा करें। यह संगठन, स्वतंत्र रूप से बाजार के रूख और उसकी व्यावहारिकता का अध्ययन करेगा अथवा मानक कार्यविधि तथा अनुमानों के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने में सहायता करेगा। इसके अलावा, यह चिह्नित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के अभिनव मैकेनिज्म का प्रस्ताव करेगा।

112. *राष्ट्रीय रेल योजना*: रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए दीर्घावधि योजना परिदृश्य की व्यवस्था करने के लिए हमने राज्य सरकारों, जन-प्रतिनिधियों तथा अन्य संगत केन्द्रीय मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से 'राष्ट्रीय रेल योजना' (एनआरपी-2030) तैयार करने का निर्णय लिया है। एनआरपी-2030 में रेल नेटवर्क का परिवहन के अन्य साधनों में सामंजस्य स्थापित करने और उन्हें एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा ताकि देशभर में निर्बाध बहुआयामी परिवहन नेटवर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करने का वातावरण बने। इससे सुरंगों तथा मेगापुल के साथ-साथ नई रेल लाइनों और नए राजमार्गों को बिछाकर परिवहन नेटवर्क की एकीकृत योजना बनाने और लागत के इष्टतमीकरण का माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न भी हासिल होगा।

एकीकरण- कांसोलिडेशन

113. *होल्डिंग कंपनी*: भारतीय रेलवे की स्वामित्व वाली कंपनियां इसकी परिसंपत्तियां हैं, जिनकी भावी संभावनाएं अथाह हैं। हम इनमें से अधिकांश कम्पनियों को एक होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्गत लाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव करते हैं, जिससे सम्मिलित संसाधनों का उपयोग करने और साथ ही प्रत्येक सहायक कंपनी की क्षमता का इस्तेमाल करने में अत्यन्त जरूरी लचीलापन मुहैया होगा।

शोध और विकास – भविष्य के लिए निवेश

114. अपने ग्राहकों को गुणवत्तापरक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलों के पास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का होना आवश्यक है। हाई स्पीड रेल, हैवी हॉल, रोलिंग स्टॉक तथा सिगनल प्रणाली जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारतीय रेलवे के लिए दुनिया की सर्वोत्तम प्रणालियों से सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित हो गया है। अल्पावधि में इन क्षेत्रों

में स्वदेशी क्षमता के विकास के लिए हमने कुछ बेहतरीन रेलों के साथ भागीदारी की है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को एक संस्थागत रूप देने तथा इससे आगे बढ़ाने के लिए सरकार, फॉरेन रेल टेक्नॉलोजी को-ऑपरेशन स्कीम (एफआरटीसीएस) को स्थापित करने का कार्य कर रही है।

115. एक शोध और विकास संगठन- स्पेशल रेलवे इस्टेब्लिसमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट (श्रेष्ठ) का गठन करने का मेरा प्रस्ताव है। अब अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) केवल दिन-प्रतिदिन के मामलों पर ही ध्यान केन्द्रित करेगा, जबकि श्रेष्ठ का लक्ष्य दीर्घकालिक शोध करना होगा। श्रेष्ठ का प्रधान एक प्रख्यात वैज्ञानिक होगा जो सीधे अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, जिसमें वैज्ञानिक और सीमित संख्या में रेलवे के विशेषज्ञ होंगे। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन का काम पूरी तरह से पारदर्शी तथा समयबद्ध परिणाम देने वाला होगा।

डाटा विश्लेषण

116. डाटा के आधार पर निर्णय लेना महान संगठनों की निशानी होती है। यद्यपि भारतीय रेलवे एक संगठन के रूप में 100 टेराबाइट्स से ज्यादा डाटा का संग्रहण करती है, इसके बावजूद इसमें अन्तर्निहित व्यवसाय के लिए इसका विश्लेषण ज्यादा नहीं किया जाता हैं। एक डेडीकेटेड क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसे स्पेशल यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एण्ड एनॉलिटिक्स (सूत्र) कहा जाएगा, का गठन किया जाएगा जो विस्तृत विश्लेषण करेगी ताकि निवेश और प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिए जा सकें। इस टीम में पेशेवर विश्लेषक और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट निर्णय लेने वालों की सहायता से इसका पूरा उपयोग किया जाएगा।

नवरचना-इनोवेशन

117. हम आन्तरिक तथा वाह्य नवरचना में सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों, स्टार्टअप्स तथा प्रगतिपरक छोटे व्यापारियों के लिए 50 करोड़ रुपए अलग से रख रहे हैं। वार्षिक आधार पर हम भारतीय रेलवे की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान, अभिनवीनता संबंधी चुनौती के माध्यम से खोजेंगे। यह अभिनव कार्य एक अभिनवीनता

समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित निवेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, रेलवे बोर्ड और श्री रतन टाटा की अध्यक्षता में "कायाकल्प" के साथ मिलकर कार्य करेगी। इस पहल कार्य के लिए एक कार्यक्रम प्रबन्धन संरचना तैयार की जाएगी। इस वर्ष के लिए, वार्षिक चुनौतियों के क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

क. निचली सतह के प्लेटफार्मों से गाड़ियों में चढ़ना
ख. सवारी डिब्बों की क्षमता बढ़ाना
ग. स्टेशनों पर डिजिटल क्षमताएं

इसके अलावा, हमारे सभी वर्कशापों तथा उत्पादन यूनिटों में नवरचना प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों तथा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सृजनात्मक अभिनव कार्यों में सहायता प्रदान की जा सके।

118. परीक्षण ट्रैक: काफी लम्बे समय से परीक्षण ट्रैक विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिससे परीक्षण की अलग-अलग स्थितियों में प्रोटोटाइप का शीघ्र परीक्षण किया जा सकेगा। यह परीक्षण इस समय मौजूदा रेलवे नेटवर्क में किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण की सभी स्थितियों में एकरूपता न लाए जा सकने के अलावा यातायात में भी विलम्ब होता है। हम परीक्षण ट्रैक तैयार करेंगे, जिसकी भारतीय रेलवे के अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी बड़ी भूमिका होगी।

अवतरण- सात मिशन

119. भारतीय रेलवे में परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल भिन्न स्तर की कार्यकुशलता के साथ इसके ढांचे में बदलाव करना अपेक्षित होगा। इसलिए, मैं 'मिशन' मोड के माध्यम से सात कार्यकलापों को शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

120. प्रत्येक मिशन का प्रधान, एक मिशन निदेशक होगा जो अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को सीधे रिपोर्ट करेगा। वह एक ऐसे क्रॉस फंक्शनल टीम का प्रधान होगा, जिसे लक्ष्य के अनुसार समय पर कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संगत निर्णय लेने का अधिकार होगा। किसी खास मिशन के लिए प्रत्येक रेलवे/उत्पादन इकाई/अ.अ.मा.सं./ केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों से नामित किए गए अधिकारी, फील्ड लेवल पर कार्यान्वयन कार्य में सहयोग करेंगे। इस मिशन के लिए वार्षिक परिणाम के आधार पर कार्य-

निष्पादन के लक्ष्य घोषित किए जाएंगे और वार्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में पूरी योजना बनाई जाएगी। ये मिशन अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक कार्यान्वयन योजनाओं को अंतिम रूप देंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

121. हम निम्नलिखित सात मिशन शुरू करेंगे:

क. मिशन 25 टन – राजस्व बढ़ाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी ढुलाई क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय हमारी अवसंरचना को 25 टन धुरा-भार को ढोने के उपयुक्त बनाना है। 2016-17 में 25 टन धुरा-भार वैगनों के जरिए 10-20% माल लदान शुरू करने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 19-20 तक 70% फ्रेट यातायात उच्च धुरा-भार वाले वैगनों में शिफ्ट करने का हमारा लक्ष्य है।

ख. मिशन जीरो दुर्घटना: इस समग्र मिशन के भाग के रूप में दो विशिष्ट सब-मिशन होंगे-

i. बिना चौकीदार वाले लेवल क्रासिंगों को समाप्त करना: भारतीय रेलों पर 40% दुर्घटनाएं तथा 68% मृत्यु के मामले लेवल क्रासिंगों पर होते हैं। इसके अलावा, इन क्रासिंगों के कारण गति भी घटती है और इस प्रकार नेटवर्क के थ्रूपुट के मामले में भी गिरावट की स्थिति बनती है। हमारी मंशा बड़ी लाइन के सभी लेवल क्रासिंगों को अगले 3-4 वर्ष में समाप्त करने की है, जिसके लिए नूतन वित्त पोषण तंत्र की व्यवस्था की जा रही है।

ii. टीसीएएस (गाड़ी टक्कररोधी प्रणाली): आमने-सामने की टक्कर की रोकथाम के लिए अब हमने देशी प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसके परिणामस्वरूप औसत खण्डीय गति बढ़ने के कारण थ्रूपुट भी बढ़ती है। हमारी मंशा अगले 3 वर्षों में उच्च घनत्व वाले नेटवर्क में 100% टीसीएएस की व्यवस्था कराने की है।

ग. *मिशन पीएसीई (खरीद और खपत में कुशलता)*: माल तथा सेवाओं की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बचत और सुधार लाने के लिए हमें अपनी खरीद प्रक्रिया को सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप बनाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया में हमारे खपत के मानदण्डों की समीक्षा की जाएगी और वेंडरों द्वारा परिचालित इन्वेंटरी, एचएसडी की

सीधी खरीद आदि जैसे कार्य व्यवहार का अधिकतम इस्तेमाल करने की संस्कृति का समावेश किया जाएगा। हम एचएसडी की खरीद तथा खपत की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें इसका रिसाव रोकना शामिल है। वर्ष 2016-17 में 1500 करोड़ रुपए से अधिक बचत करने का भी हमारा लक्ष्य है। हम स्क्रैप को चिह्नित करने और उसका निपटान करने की एक नई पद्धति भी बनाएंगे।

घ. *मिशन रफ्तार*: रेलवे प्रणाली का थ्रूपुट टन भार तथा रफ्तार पर निर्भर है। मिशन रफ्तार, 25 टन का पूरक होगा, जिसमें माल गाड़ियों की औसत रफ्तार दुगुनी करने और सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस आदि गाड़ियों की रफ्तार को अगले 5 वर्ष में 25 किमी. प्रति घंटा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाएगा। सभी लोको कर्षित पैसेंजर गाड़ियों के स्थान पर अगले पांच वर्षों में डीईएमयू/एमईएमयू गाड़ियां चलाने के प्रयास किए जाएंगे।

ड. *मिशन शतक* – भारतीय रेलवे का 85% यातायात, प्राइवेट साइडिंगों और फ्रेट टर्मिनलों से प्राप्त होता है। 400 से ज्यादा प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त हुए हैं, जो अलग-अलग चरणों में हैं। अगले 2 वर्षों में हम कम से कम सौ साइडिंगों को चालू कर देंगे। वर्तमान साइडिंग/पीएफटी नीति को संशोधित किया जाएगा ताकि और ज्यादा निजी भागीदारी प्राप्त की जा सके और शक्तियों के विकेंद्रीकरण सहित सभी नए आवेदनों को स्वीकार करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए ऑन-लाइन पोर्टल परिचालित किया जाएगा।

च. मिशन बुक कीपिंग से आगे: एक सरकारी उपक्रम होने के कारण भारतीय रेलवे, लेखांकन में पद्धतियों का पालन नहीं करती है, जिससे यूनिट लागत के विस्तृत आकलन में सहायता मिलती है। हालांकि हम एकल एन्ट्री से दोहरी एन्ट्री प्रणाली और कैश आधारित के स्थान पर पूर्णतया अर्जन आधारित प्रणाली को अपना रहे हैं, तथापि मैं उन्हें बड़ा सुधार नहीं मानता हूँ। समृद्ध वाणिज्यिक उद्यम के रूप में हम चाहेंगे कि भारतीय रेलवे एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसी लेखांकन प्रणाली बनाएं,

जिसमें परिणामों को निवेश से सम्बद्ध किया जा सके। यह एक संरचनात्मक परिवर्तन है जो हमारे परिवर्तन लाने के प्रयासों का आधार है क्योंकि सही लेखांकन से सही लागत निर्धारण होता है और इस प्रकार सही मूल्य निर्धारण तथा सही परिणाम प्राप्त होते हैं। हमारी मंशा इसका रेलवे पर कार्यान्वयन मिशन मोड में शुरू करने और अगले कुछ वर्षों में इसे पूरी तरह कार्यान्वित करने की है।

छ. मिशन क्षमता उपयोग: 2019 तक दो डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोरों को चालू कर दिया जाना निर्धारित है। इससे दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता के बीच भारी क्षमता में माल-यातायात की ढुलाई के लिए नई क्षमता सृजित होगी। मौजूदा रेलपथों से नए कोरिडोरों में माल गाड़ियों को शिफ्ट करने से मौजूदा मार्गों में काफी क्षमता रिलीज हो जाएगी, जिससे इन ट्रंक मार्गों पर यात्री सेवाओं के स्वरूप में सुधार करने में सहायता मिलेगी। इन्हें चालू करने से पहले इस भारी नई क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए ब्लू-प्रिंट तैयार करने का प्रस्ताव है।

सामाजिक पहल और सहारा कार्य

मानव संसाधन/कौशल

122. मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मैं एक ऐसे कार्यबल का मुखिया हूँ जो ईमानदार और समर्पित है। मेरा निरन्तर प्रयास रहता है कि उनके कार्यों की परिस्थिति में सुधार किया जाए ताकि वे निरंतर निष्ठापूर्ण ढंग से संगठन की सेवा कर सकें। रेलवे अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के बीच आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता करेंगे। हम 5 रेलवे अस्पतालों में 'आयुष' प्रणाली शुरू करेंगे।

123. हमारे सभी गैंगमैनों को एक उपकरण दिया जाएगा जिसे 'रक्षक' कहा जाएगा। यह उपकरण वायरलेस समर्थित होगा और इससे उन्हें आने वाली गाड़ियों के बारे में सूचना प्राप्त होगी। हम वैल्यू इंजीनियरिंग के जरिए, रक्षकों द्वारा पैदल पेट्रोलिंग के समय ढोए जाने वाले औजारों का भार भी कम करेंगे। हम अपने लोको पायलटों के लिए कैब में प्रसाधन एवं वातानुकूलन की भी व्यवस्था करेंगे।

124. नीति विषयक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम दो पीठों की स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं - एक महत्वपूर्ण वित्त, अनुसंधान एवं नीति विकास से संबंधित सी टी वेणुगोपाल पीठ और दूसरी भारतीय रेलवे के लिए जियो स्पेटल प्रौद्योगिकी से संबंधित कल्पना चावला पीठ।

125. नई सोच और विचार से भरपूर और ऊर्जावान अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्येक वर्ष इंजीनियरी एवं एमबीए स्कूलों के 100 छात्रों को 2-6 महीनें की इंटर्नशिप देंगे।

126. कौशल विकास मंत्रालय के साथ भागीदारी करके हम अपने परिसरों में विशाल कौशल विकास पर कार्य करेंगे। रेल कारखाने एवं उत्पादन इकाइयों में "कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट केन्द्र" विकसित किए जाएंगे, जिसमें आम जनता के लिए एक/दो विशिष्ट गतिविधियां होंगी। हम रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों सहित दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को कुशल बनाने के लिए प्रतिष्ठित एनजीओ के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

सामाजिक पहल

127. पिछले वर्ष मैंने विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी से सामाजिक मुद्दों जैसेकि स्टेशनों पर साफ-सफाई तथा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने में भारतीय रेलवे की सहायता करने की अपील की थी। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि कई स्वैच्छिक ग्रुप आगे आए और उन्होंने इस राष्ट्रीय अभियान में अपना योगदान दिया। मैं उन सबके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आगे भी उनका सहयोग मिलते रहने की आशा करता हूँ।

128. स्वयं सहायता ग्रुप न केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं बल्कि ये उन्हें सम्मान तथा गरिमा भी प्रदान करते हैं। आईआरसीटीसी ने केटरिंग एवं कुकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वयं सहायता ग्रुपों का पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ भागीदारी कर रहे हैं, जिससे आईआरसीटीसी वेबसाइट की सहायता से तथा उसे एक्सेस करके इन स्वयं सहायता ग्रुपों द्वारा निर्मित उत्पादों की व्यापक ई-मार्केटिंग सुनिश्चित हो सके, जिससे ग्रामीण आय में बढ़ोतरी होगी।

129. हमने रोजगार के सृजन में सहायता करने और ग्रामीण भारत में आत्म- निर्भरता लाने के लिए खादी ग्रामोद्योग निगम के साथ भागीदारी की है, जिसके परिणामस्वरूप 17 लाख

श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। हम यात्रियों के लिए उत्पाद तैयार करने तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ निरंतर भागीदारी करेंगे और भारतीय रेलवे के विशाल संसाधनों तथा परिसम्पत्ति का इस्तेमाल करके उनका विपणन भी करेंगे। हम एससी/एसटी उद्यमियों से उत्पादों के स्रोत को प्रोत्साहित करेंगे।

पर्यावरण

130. कार्बन फुट प्रिंट को कम करने की भारत की वचनबद्धता के परिप्रेक्ष्य में, हमने ऊर्जा ऑडिट की है, जिसमें गैर-कर्षण क्षेत्र में ऊर्जा खपत 10% से 15% तक कम होने की संभावना का पता चला है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने विश्चिश्य किया है कि बिजली की नई व्यवस्था में केवल एलईडी लाइट की ही व्यवस्था की जाएगी और सभी रेलवे स्टेशनों पर आगामी 2 से 3 वर्षों में एलईडी लाइटें लगा दी जाएंगी।

131. पर्यावरणीय मान्यता, जल प्रबंधन और कूड़े-कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। अब तक हमने 2000 से अधिक स्थानों पर वर्षा जल संग्रहण (आर डब्ल्यू एच) की सुविधा मुहैया कराई है और 200 वर्ग मीटर से अधिक के छतवाले सभी प्रतिष्ठानों में आर डब्ल्यू एच प्रणाली की चरणबद्ध ढंग से व्यवस्था की जाएगी, यह कदम उठाने के पीछे इस बात का अहसास था कि प्रतिदिन लगभग 250 मिलियन लीटर पानी की रीसाईकिलिंग की कुल क्षमता में से, इस समय हम केवल 20 मिलियन लीटर पानी की ही रीसाईकिलिंग कर रहे हैं।

132. भारतीय रेल स्टील के पुलों पर स्टील के स्लीपरों का इस्तेमाल करती है, जिस पर अनुरक्षण और उच्च गति पर प्रतिबंध है, इसलिए रीसाईकिलिंग प्लास्टिक वेस्ट से तैयार पर्यावरण हितैषी संयुक्त स्लीपर विकसित किए गए हैं, जो सभी गर्डर पुलों में इस्तेमाल किए जाएंगे।

133. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के विज़न को आगे ले जाने के लिए भारतीय रेल ने आगामी 5 वर्षों में 1000 मेगावॉट की क्षमता वाले ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा था। छतों पर 50 मेगावॉट ऊर्जा संयंत्रों के लिए नीति विषयक मार्ग-निदेश और निविदा प्रलेख जारी कर दिए गए हैं और अन्य 100 मेगावॉट की स्थापना की जा रही है। हमने जैसलमेर में 25 मेगावॉट का पवन चक्की बिजली संयंत्र लगा दिया है और हम अगले वर्ष 132.5 मेगावॉट चालू करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सौर माइक्रो-

ग्रिड की पायलट आधार पर संस्थापना करने के लिए दूर-दराज में स्थित रेलवे स्टेशनों के लिए अपनी अवसंरचना का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव करते हैं, जो रेलवे स्टेशनों को न केवल सुदृढ़ एवं विश्वसनीय बिजली की सप्लाई करेगी बल्कि निकटवर्ती क्वार्टरों और आस-पास वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में भी सहायक होगी।

134. हम 500 से अधिक सवारी-डिब्बों को खड़ा करने के लिए प्रमुख कोचिंग डिपुओं में ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट स्थापित करेंगे। इससे पानी की कम खपत में बेहतर धुलाई होगी। इसके अलावा, आगामी वर्षों में वॉटर रीसाईकिलिंग संयंत्रों की संस्थापना के लिए 32 स्टेशन और 10 कोचिंग डिपुओं की पहचान की गई है।

135. हरित औद्योगिक इकाइयां : सभी उत्पादन इकाइयों और प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में कम से कम एक कारखाने को संगत प्रमाणन, ऊर्जा के कुशल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जल संरक्षण, बेहतर हरियाली तथा रद्दी के पर्यावरण हितैषी प्रबंधन के जरिए एक हरित औद्योगिक इकाई के रूप में बदलने का प्रस्ताव है।

136. विभिन्न रेल कार्यालयों को पर्यावरण महत्व की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने क्षेत्रीय रेलवे या उत्पादन इकाई को पर्यावरण के संबंध में उत्कृष्ट कार्य करने पर एक शील्ड देना शुरू किया है।

पर्यटन

137. पर्यटन में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं हैं। हम पर्यटक सर्किट गाड़ियां चलाने के लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेंगे और राजस्व की भागीदारी के मॉडल की संभावनाओं का पता लगाएंगे। हमने हाल ही में राष्ट्रीय रेल

संग्रहालय को अपग्रेड किया है। रेलवे संग्रहालयों और यूनेस्को विश्व धरोहर रेलों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा।

138. भारत की संपन्न जीव विविधता एवं वन्यजीव, अतुल्य भारत अभियान का एक मुख्य आधार हैं। पिछले वर्ष हमने हाथियों की दुर्घटनाओं के मामले में कमी करने, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, के लिए एक परियोजना शुरू की थी। इस वर्ष अपने राष्ट्रीय पशु, बाघ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ वाले वन्यजीव उद्यान को जोड़ते हुए एक पूरे पैकेज का प्रस्ताव देंगे, जिसमें गाड़ी यात्रा, सफारी एवं आवास शामिल होगा।

<u>निष्कर्ष</u>

139. अध्यक्ष महोदया, रेलवे प्रणाली समूचे भारत का प्रतिबिम्ब है। इसमें हमारे महान देश का मूल स्वभाव, नैतिक मूल्य और आचार-व्यवहार शामिल हैं। यह हमारे विकासशील देश के अथक उत्साह, शाश्वत आशा, आकांक्षाओं, सतत् प्रयास, दृढ़ संकल्प और अनंत उमंग का परिचायक है। जिसने भी कहा है कि भारत में रेलवे जीवन का अभिन्न अंग है, बिल्कुल ठीक कहा है।

140. अध्यक्ष महोदया, मैंने अपना भाषण पिछले वर्ष शुरू की गई यात्रा, भारतीय रेल के बदलाव की यात्रा से शुरू किया था। हमने इस बदलाव के सभी पहलुओं, स्केल से स्पीड, सफाई से कार्यकुशलता और संसाधन जुटाने में बहुत अधिक प्रगति हासिल की है। अभी हमें बहुत लम्बा रास्ता तय करना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास मजबूत इरादा है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा है।

जब तक ध्येय पूरा न होगा, तब तक पग की गति न रूकेगी।
आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी।

- श्री अटल बिहारी वाजपेयी

141. अपने इस सफर के दौरान, मुझे गौतम बुद्ध का स्मरण हो रहा है, जिन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति यात्रा करता है, वह दो गलतियां कर सकता है: पहली यात्रा शुरू ही न करे और दूसरी सफर पूरा न करे। हम अपना सफर पहले ही शुरू कर चुके हैं और मैं इस यात्रा को पूरा भी करना चाहता हूँ। हम भारतीय रेल को समृद्धि अथवा सफलता की मंजिल तक पहुंचाने से पहले नहीं रुकेंगे।

अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं 2016-17 का रेल बजट माननीय सदन में संस्तुत करता हूँ।

****

अनुलग्नक- I

अध्यक्ष महोदया, अब मैं माननीय सदन के समक्ष 2015-16 का वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता हूं:

वित्तीय निष्पादन 2015-16

अध्यक्ष महोदया, सकल यातायात प्राप्तियों में 1,83,578 करोड़ रु. के बजट अनुमान लक्ष्य की तुलना में संशोधित अनुमान 2015-16 में 15,744 करोड़ रु. की शुद्ध कमी हुई है। वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान में यात्री यातायात में आमदनी में 16.7% की वृद्धि निर्धारित की गई थी। बहरहाल, चूंकि वर्ष 2014-15 में यात्री यातायात से आमदनी संशोधित अनुमान लक्ष्य की तुलना में कम रही इसलिए वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक वृद्धि का लक्ष्य 18.9% रखा गया था। वर्ष 2013-14 से उपनगरीय और गैर-उपनगरीय यात्रा के दोनों पीआरएस क्षेत्रों में लगातार नकारात्मक वृद्धि के रूख को ध्यान में रखते हुए इसमें कमी की गई है। इसी प्रकार, माल यातायात से आमदनी में, यद्यपि 2015-16 के बजट अनुमान 1186.25 मिलियन टन के लदान लक्ष्य और 626 किमी. की औसत दूरी के साथ 1,21,423 करोड़ रु. निर्धारित किए गए थे, लेकिन कोर सेक्टर से कम मांग के कारण इस क्षेत्र में वृद्धि प्रभावित हुई जिसके परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान 2015-16 में इस लक्ष्य को 1,11,853 करोड़ रु. पर पुनः निर्धारित करना पड़ा।

इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देखे गए रूख से बजट में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में यातायात आमदनी में कमी को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न उपाय अपनाने के लिए सावधान हो गए ताकि साधारण संचालन व्यय (ओडब्ल्यूई) पर नियंत्रण रखा जा सके। हमने वस्तुसूची, परिवर्तनीय लागतों और आकस्मिक व्यय जैसे नियंत्रणीय शीर्षों के संदर्भ में कड़े किफायती और मितव्ययिता उपाय शुरू किए, जिनके कारण 1,19,410 करोड़ रु. के बजट में निर्धारित साधारण संचालन व्यय वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान में घटकर 1,10,690 करोड़ रु. हो गया अर्थात् इसमें8,720 करोड़ रु. की गिरावट आई। संचालन व्यय में बचत से हमें रेलवे ऋण अदायगी निधि में 7वें वेतन आयोग के लिए विनियोग के प्रावधान के लिए मदद मिली है। अतः, संशोधित अनुमान 2015-16 में साधारण संचालन व्यय में मात्र 4.4% की वृद्धि हुई। भारतीय रेल पर 13.79 लाख कुल पेंशनभोगी हैं। बजट अनुमान से पेंशन निधि

में 34,900 करोड़ रु. का विनियोजन संभव हुआ। बहरहाल, इस रूख के आधार पर, संशोधित अनुमान में पेंशन के रूप में व्यय में 34,500 करोड़ रु. की मामूली सी कमी हुई है।

आंतरिक संसाधन सृजन में कमी आई और तदनुसार, 7,900 करोड़ रु. की व्यवस्था करके 2015-16 के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 5,500 करोड़ रु. की कमी की गई है। वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान में व्यय की तुलना में आमदनी का आधिक्य 11,402.40 करोड़ रु. है। उक्त अनुमान के परिणामस्वरूप, संशोधित अनुमान में निर्धारित परिचालन अनुपात 2013-14 में 93.6% और 2014-15 में 91.3% की तुलना में 90.0% है। वर्ष 2015-16 के लिए योजना आकार अर्थात् बजट अनुमान स्तर पर 1,00,000 करोड़ रु. आंका गया है।

महोदया, अब मैं 2016-17 के लिए बजट अनुमान पेश करता हूं:

बजट अनुमान 2016-17:

वर्ष 2016-17 में, राजस्व में वृद्धि और उपयुक्त निवेश सुनिश्चित करने की मंशा है जिससे 2015-16 में शुरू किए गए भीड़भाड़ कम करने और लाइन क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यों को जारी रखा जा सकेगा। परियोजनाओं को सुनिश्चित धनराशि मुहैया कराने के लिए बढ़े हुए पूंजी व्यय पर बल दिया गया है, जिसमें वित्त व्यवस्था के विभिन्न स्रोतों का मिश्रण है।

सकल यातायात प्राप्तियां 1,84,820 करोड़ रु. रखी गई हैं। यात्री यातायात से आमदनियां 12.4% पर निर्धारित की गई है और तदनुसार आमदनी संबंधी लक्ष्य 51,012 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में लाभप्रद वृद्धि की प्रत्याशा में माल यातायात 50 मिलियन टन के वर्धमान यातायात पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, माल यातायात से आमदनी 1,17,933 करोड़ रु. प्रस्तावित की गई है। अन्य कोचिंग एवं विविध आमदनियां क्रमशः 6,185 करोड़ रु. और 9,590 करोड़ रु. निर्धारित की गई है।

साधारण संचालन व्यय के अंतर्गत, साधारण वृद्धि की व्यवस्था के अलावा, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में साधारण संचालन व्यय के लिए मौजूदा राजस्व से 1,23,560 करोड़ रु. की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसमें 3,000 करोड़ रु. की उधार राशि शामिल है जिसकी व्यवस्था रेलवे ऋण सेवा निधि (डीएसएफ) के निकासी के जरिए की जानी है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2016-17 में पेंशन निकासी 45,500 करोड़ रु. निर्धारित की गई है। उच्चतर कर्मचारी लागत और पेंशन दायिता से रेलों की आंतरिक संसाधन स्थिति प्रभावित होती है। तदनुसार, राजस्व से मू.आ.नि. को विनियोजन 3,200 करोड़ रु. और उत्पादन इकाइयों से 200 करोड़ रु. रखा गया है। शुद्ध आधार पर मू.आ.नि से 3,160 करोड़ रु. की निकासी का प्रस्ताव है, यद्यपि वार्षिक योजना में मू.आ.नि रु. पूरा किया जाने वाला सकल व्यय 7,160 करोड़ रु. आंका गया है। पूंजी निधि को 5,750 करोड़ रु. विनियोजित करने का प्रस्ताव है। इस निधि में पूर्ववर्ती शेष से 1,250 करोड़ रु. की कमी के कारण आईआरएफसी को पट्टा प्रभारों के मूल घटक के भुगतान के लिए 7,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है।

वर्ष 2016-17 में रेलवे 1,21,000 करोड़ रु. का योजना आकार प्रस्तावित करती है।

अनुलग्नक-2

2015-16 की बजट उद्घोषणाओं का कार्यान्वयन			
क्र.सं.	**भाषण पैरा सं.**	**बजट घोषणा का कार्यान्वयन**	**स्थिति**
1.	16	हम अपने स्टेशनों और गाड़ियों की सफाई के लिए एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव करते हैं।	पर्यावरण एवं हाऊसकीपिंग निदेशालय गठित किया गया।
2.	16	रेलवे की योजना है कि बड़े कोचिंग टर्मिनल के समीप "अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा" पैदा करने वाले संयंत्रों को स्थापित किया जाए जिससे पर्यावरण अनुकूल विधि से अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किया जा सके।	जयपुर और नई दिल्ली दो स्टेशनों के लिए रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) निविदा खोली गई। 31 मार्च 2016 तक निविदा आबंटित की जानी है।
3.	17	हम विगत वर्ष के 120 स्टेशनों की तुलना में 650 अतिरिक्त स्टेशनों पर नए शौचालय बनाएंगे।	295 स्टेशनों पर 407 अतिरिक्त शौचालय बनाए गए, जिन्हें इस वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
4.	17	सवारी डिब्बों में जैव-शौचालय फिट किए जा रहे हैं। अभी तक हमने मौजूदा शौचालयों के स्थान पर 17,388 जैव-शौचालयों को लगा दिया है। इस वर्ष हमारा इरादा और 17,000 जैव शौचालयों का प्रावधान करने का है।	10,250 जैव शौचालय फिट किए गए। 31 मार्च 2016 तक लक्ष्य पूरा किया जाना है।
5.	17	अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) को छह माह के भीतर वैक्यूम शौचालयों का अभिकल्प तैयार करने का कार्य दिया गया है।	डिब्रूगढ़ राजधानी में विश्व का पहले वैक्यूम जैव शौचालय का ट्रायल रन किया गया। परीक्षण पूरा होने के बाद इसका विस्तार किए जाने की योजना है।
6.	18	यद्यपि, भारतीय रेलवे की ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) जो इस समय 500 जोड़ी गाड़ियों में उपलब्ध है, को और प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है, हम ग्राहकों की चिंताओं के समाधान के लिए तुरंत छोटे-छोटे कदम उठाएंगे।	मौजूदा वर्ष में 74 अतिरिक्त जोड़ी गाड़ियों में ओबीएचएस सुविधा मुहैया कराई गई। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत इसमें अन्य 400 गाड़ियों को शामिल किया जाना है, इसके लिए लगभग 1000 गाड़ियों का लक्ष्य रखा गया है।
7.	18	बिस्तर के साथ डिस्पोजेबल बैग प्रदान करने की व्यावहारिकता पर भी विचार किया जा रहा है ताकि यात्री अपने कूड़े को उसमें डाल सकें।	उत्तर, दक्षिण पूर्व, पूर्व, दक्षिण पश्चिम रेलों में प्रारम्भिक तौर पर किया जा रहा है।
8.	18	गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों में भी डस्टबिनों को लगाया जाएगा।	सभी नए सवारी डिब्बों में क्रियान्वित कि गया; 5000 सवारी डिब्बों में रेट्रो-फिटमे

			की योजना है।
9.	20	हम आगामी छह महीने के भीतर बिस्तरों के डिजाइन, गुणवत्ता तथा साफ-सफाई के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेंगे।	निफ्ट दिल्ली ने डिजाइन प्रस्तुत कर दिया है जिसके लिए सभी अनुमोदन प्रदान कर दिए गए हैं। इस वित्त वर्ष में चुनिंदा गाड़ियों में शुरू किया जाएगा।
10.	20	चुनिंदा स्टेशनों पर डिस्पोजेबल बिस्तर की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भुगतान के आधार पर आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से सभी यात्रियों को प्रदान की जा रही है।	सुविधा शुरू कर दी गई है।
11.	20	हम मैकेनाइज्ड लांड्रियों की संख्या बढ़ाएंगे।	इस वर्ष 6 लांड्रियां लगा दी गई हैं, 31 मार्च 2016 तक 4 और लांड्रियां लगाने की संभावना है।
12.	21	यात्रियों की समस्याओं का वास्तविक समय के आधार पर निराकरण करने के लिए अखिल भारतीय 24X7 हैल्पलाइन नं.138 कार्य करना आरंभ कर देगी।	कार्यान्वित
13.	21	रेलवे शिकायतों का समाधान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया जा रहा है।	कार्यान्वित
14.	21	सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नंबर 182 निर्धारित किया है।	कार्यान्वित
15.	21	रेलवे अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि के लिए निर्भया निधि से संसाधनों का उपयोग करेगी।	1000 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अंतिम निधि क्लियरेंस की प्रतीक्षा है।
16.	22	आशोधित "हॉट बटन" कॉइन वैंडिंग मशीनों और "सिंगल डेस्टिनेशन टेलर" विंडो से लेनदेन में लगने वाले समय में काफी कमी होगी।	कार्यान्वित

17.	22	भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वे एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद रियायती ई-टिकट खरीद सकते हैं।	कार्यान्वित
18.	22	बहु-भाषी ई-टिकटिंग पोर्टल विकसित करने की दिशा में कार्य करने का भी प्रस्ताव है।	हिंदी में कर दिया गया है। 4 अन्य भाषाओं में शुरू करने की योजना बनाई गई है।
19.	23	आशा है कि हम सभी स्टेशनों पर एटीवीएम सुविधा को उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध करा देंगे।	1780 एटीवीएम और 225 कैश कॉइन व स्मार्ट कार्ड परिचालित टिकट वेंडिंग मशीनें चालू कर दी गई हैं।
20.	23	हमने स्मार्ट फोनों पर अनारक्षित टिकट को जारी करने की एक पायलट परियोजना पहले ही शुरू कर दी है। आशा है कि हम उत्तरोत्तर इस सुविधा को सभी स्टेशनों पर उपलब्ध करा देंगे।	दक्षिण पूर्व, पूर्व, दक्षिण मध्य, उत्तर रेलों में कार्यान्वित
21.	23	डेबिट कार्ड द्वारा परिचालित होने वाली मशीनों को शुरू करने का प्रस्ताव है।	कार्यान्वित
22.	24	हमारे बहादुर सिपाहियों के लाभ के लिए वारंट को समाप्त करने के लिए रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है। लगभग 2000 स्थानों में से 600 स्थानों पर इस सुविधा को चालू कर दिया गया है। इस सुविधा का और विस्तार किया जाएगा।	सभी 2400 रक्षा यूनिटों को एनजीईटी आधारित रक्षा यात्रा प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए रक्षा मंत्रालय से साफ्टवेयर रिफाइनमेंट प्रक्रियाधीन है।
23.	25	हमारा यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट मंडलों में बेस किचन स्थापित करने का भी इरादा है, जिन्हें अत्यंत विश्वसनीय एजेंसियों द्वारा चलाया जाएगा।	कार्यान्वित
24.	26	इस समय वाटर-वेंडिंग मशीन अपर्याप्त हैं। हम इसे अधिकांश रेलवे स्टेशनों में लगाएंगे।	मशीनें लगाने का कार्य जारी है और 31 मार्च 2016 तक 2500 मशीनें लगाई जानी हैं।

25.	27	चल टिकट परीक्षकों को हैंड हेल्ड टर्मिनल उपलब्ध कराएंगे जिसका उपयोग यात्रियों का सत्यापन और चार्टों को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकेगा।	परीक्षण सफल रहा और अधिकांश शताब्दी गाड़ियों में परियोजना कार्यान्वित की गई। इसे चरणों में अन्य गाड़ियों में लगाया जाएगा।
26.	28	हम एक एकीकृत ग्राहक पोर्टल तैयार कर रहे हैं, जो ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक सिंगल इंटरफेस होगा।	कार्यान्वित
27.	29	केंद्रीय रूप से नियंत्रित रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क को अगले दो वर्षों में 2000 से ज्यादा स्टेशनों पर लागू कर देने की संभावना है, जो सूचना मुहैया कराने में सहायता प्रदान करेगा।	10 स्टेशनों पर प्रूफ प्राप्त हो गया है, इसे 31 मार्च 2016 तक शुरू किया जाना है।
28.	30	हमारा यात्रियों को पहले ही गाडियों के आगमन/प्रस्थान के अद्यतन समय की जानकारी देने के लिए "एसएमएस अलर्ट" सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है।	राजधानी और दूरांतों गाड़ियों में पहले ही शुरू किया जा चुका है।
29.	30	इसी प्रकार, गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के आगमन से 15/30 मिनट पहले ही "एसएमएस अलर्ट" भेजा जाएगा।	राजधानी और दूरांतों गाड़ियों में पहले ही शुरू किया जा चुका है।
30.	31	महिला यात्रियों की संरक्षा के लिए पायलट आधार पर मेनलाइन के चुनिंदा सवारी डिब्बों और उपनगरीय गाडियों में महिलाओं के डिब्बों में निगरानी रखने के लिए कैमरा लगाए जाएंगे परंतु ऐसा करते समय उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा।	मुंबई उपनगर में पायलट परियोजना शुरू की गई। इस वित्त वर्ष में इसे शान-ए-पंजाब गाड़ी में शुरू किया जाएगा।
31.	32	मनोरंजन सुविधा का विस्तार सभी शताब्दी गाडियों में किया जाएगा।	एक शताब्दी गाड़ी में पहले से ही उपलब्ध है। यह सुविधा 31 मार्च 2016 तक 6 अन्य शताब्दी गाड़ियों में शुरू की जाएगी।
32.	33	साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बों में मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी और स्लीपर श्रेणी के सभी सवारी डिब्बों में चार्जिंग सुविधाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी।	सभी नए सवारी डिब्बों में कार्यान्वित, 1718 स्लीपर और 746 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों में रेट्रो फिटमेंट पूरा हो गया है। इसका क्रियान्वयन पूरे जोरों पर है।

33.	34	आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत 200 और स्टेशनों को शामिल करने का प्रस्ताव है।	कार्यान्वित
34.	35	सभी ए1 और ए कोटि के स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया पहल के भाग के रूप में "बी" कोटि के स्टेशनों पर भी वाई-फाई मुहैया कराया जाएगा।	11 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है। दिसंबर 2016 तक और 100 स्टेशनों पर की जाएगी।
35.	36	विश्राम कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही शुरू कर दी गई है।	अधिकांश स्टेशनों को कवर करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग का विस्तार किया गया।
36.	36	स्टेशनों पर धीरे-धीरे स्वयं परिचालित किए जाने वाले लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।	पांच स्टेशनों पर शुरू किया गया
37.	36	प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता के लिए उन्हें लाने तथा छोड़ने के लिए आईआरसीटीसी के माध्यम से पिक-अप एवं ड्रॉप सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है।	22 स्टेशनों पर कार्यान्वित
38.	36	हम वरिष्ठ नागरिकों, रोगियों और भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी के माध्यम से चुनिंदा स्टेशनों पर भुगतान के आधार पर व्हील चेयर की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी मुहैया कराएंगे।	कार्यान्वित
39.	37	गाड़ियों में कंफर्म सीटों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्दि करके अधिक से अधिक बर्थें उपलब्ध कराई जाएंगी।	स्थायी आधार पर 884 सवारी डिब्बों का संवर्द्धन करके 65000 अतिरिक्त बर्थ लगाई गईं।
40.	37	निर्धारित गाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उनमें मौजूदा 24 सवारी डिब्बों के स्थान पर 26 सवारी डिब्बे जोड़े जाएंगे।	क्षमता संवर्द्धन के लिए 5 गाड़ियों की पहचान की गई है। मुख्य संरक्षा आयुक्त, नागर विमानन मंत्रालय से स्वीकृति प्रतीक्षित है।
41.	37	आम जनता के हित के लिए निर्धारित गाड़ियों में जनरल श्रेणी के अधिक सवारी डिब्बे जोड़े जाएंगे।	स्थायी आधार पर सामान्य श्रेणी के 390 अनारक्षित सवारी डिब्बों का संवर्द्धन किया गया।

42.	38	मुंबई उपनगरीय खंड पर चल रहे परीक्षणों के व्यापक आकलन के बाद वातानुकूलित ईएमयू सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव है।	31 मार्च 2016 तक सेवा शुरू की जानी है।
43.	39	उपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सीढियों का मौजूदा डिजाइन जो यात्रियों के अनुकूल नहीं होता है, को बदल देंगे।	आईसीएफ में नई सीढ़ी का डिज़ाइन बनाया गया और नए सवारी डिब्बों में यह सुविधा होगी।
44.	39	बहरहाल, अल्पकालिक उपाय के रूप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली बर्थों में कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव है।	कार्यान्वित
45.	39	चल टिकट परीक्षकों को भी निचली बर्थ प्राप्त करने में वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की मदद करने की हिदायत दी गई हैं।	कार्यान्वित
46.	39	सवारी डिब्बों में एक फोल्डिंग सीढ़ी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि चढ़ने में आसानी हो।	प्रथम एसी श्रेणी में पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं।
47.	39	संरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीच के सवारी डिब्बे आरक्षित किए जाएंगे।	कार्यान्वित
48.	40	ग्राहकों को यात्रा का सुखद अनुभव के लिए बेहतर कोच डिजाइन और इंटीरिअर पर जोर दिया जाएगा।	मॉडल रेक तैयार हो गया है। नए सवारी डिब्बों वाली महामना एक्सप्रेस शुरू की गई।
49.	40	सभी सवारी डिब्बों के स्थान पर उत्तरोत्तर एलएचबी डिजाइन के सवारी डिब्बे लगाने का भी हमारा विचार है।	अनुदेश जारी किए गए। आईसीएफ में नई सुविधा शुरू की गई। 2015-16 में 1248 एलएचबी सवारी डिब्बे उपलब्ध होंगे।
50.	41	बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त करने और यात्रा समय में लगभग 20% की कमी करने के उद्देश्य से एक आधुनिक गाड़ी प्रणाली जिसे ट्रेन सेट कहते हैं, को शुरू करने का प्रस्ताव है। ये बुलेट ट्रेन के समान है और इन्हें इंजन के बिना मौजूदा रेलपथ पर चलाया जा सकता है। इसके	आरएफक्यू को अंतिम रूप दिया गया और वित्तीय बोली लगाने के लिए बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो प्रतीक्षित है।

		परिणामस्वरूप रेलवे पर उच्चतर क्षमता उपलब्ध होगी, उर्जा की बचत होगी और थ्रू-पुट में वृद्धि होगी। हम आशा करते हैं कि अगले 2 वर्षों के भीतर हमारी प्रणाली पर इन गाड़ियों का पहला सेट दौड़ने लगेगा। इसके अनुभव के आधार पर भारत में गाड़ी सेटों के विनिर्माण के बारे में विचार किया जाएगा। हमारा प्रत्येक भारतीय तक काम तथा जॉब का विस्तार करने का प्रस्ताव है।	
51.	42	वृद्ध और भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए बड़े स्टेशनों पर लिफ्टों और एस्केलेटरों की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।	2015-16 में 60 एस्केलेटर और 25 लिफ्ट चालू की जानी हैं। 40 एस्केलेटर लगाने का कार्य चल रहा है।
52.	42	भविष्य में विनिर्मित सभी नए सवारी डिब्बों में ब्रेल की सुविधा होगी	कार्यान्वित
53.	42	भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों की सुविधा के लिए चौड़े प्रवेश द्वार बनाने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए कहा गया है।	कार्यान्वित
54.	44	हमारा प्रत्येक रेलवे में मंडल समिति बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी अध्यक्षता संसद सदस्य द्वारा की जाएगी, जो रेलवे और भारत की जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे।	कार्यान्वित
55.	46	यद्यपि पहले से चुने गए स्टेशनों के विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी, तथापि शेष स्टेशनों के लिए हम स्टेशन पुनर्विकास नीति में पूर्णतया बदलाव करने और इच्छुक पार्टियों से खुली निविदाएं आमंत्रित करके शीघ्र पुनर्विकास के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव करते हैं। रियायती दरों पर स्थान और नभ अधिकारों का लाभ उठाने हेतु विकास करने के लिए मौजूदा स्टेशन 'जैसा है जहां हैं' आधार पर उपलब्ध रहेंगे। भूमि बेची नहीं जाएगी। इन स्टेशनों पर चलती गाड़ियों के लिए रेलवे की परिचालनिक आवश्यकताएं मुहैया कराके अपने डिज़ाइन और	1. कैबिनेट से अनुमोदन मिल गया है। 2. वेबसाइट पर डाटा अपलोड कर दिया गया है। 3. मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। 4. एनबीसीसी को 3 स्टेशन सौंपे जाएंगे। 5. स्टेशन पुनर्विकास के लिए विश्व बैंक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर विचार कर रहा है।

		कारोबारी सुझावों के साथ इस बोली प्रक्रिया में कोई भी भाग ले सकता है। सभी बोलियों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा कार्रवाई की जाएगी और वेब पर अपलोड और बोली संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों से समेकित किया जाएगा। शीघ्र निर्णय करने के लिए क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कक्ष की स्थापना की जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे रेलवे स्टेशन देखने में सुंदर लगे और उनकी इमारतों में उस शहर की संस्कृति और कला झलकती हो। हम राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को इस प्रयास में सहयोग के लिए अपील करते हैं।	
56.	47	बड़े शहरों में स्थित अधिकांश रेलवे टर्मिनल अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र है। बड़े शहरों में सैटेलाइट रेलवे टर्मिनलों के विकास का प्रस्ताव है, जिससे भीड़-भाड़ कम करने के साथ-साथ उपनगरों में बसने वाले यात्रियों को सेवाएं उपलब्ध कराने का दोहरा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। इन सैटेलाइट टर्मिनलों पर आरंभिक और टर्मिनेटिंग गाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं होगी, जो मौजूदा बड़े टर्मिनलों पर भी थोड़े समय के लिए रुकेंगी। इस प्रयोजन के लिए 2015-16 में दस चुनिंदा स्टेशनों पर कार्य शुरू किया जाएगा।	11 शहरों में 16 स्टेशनों पर कार्य शुरू किया गया। अन्य 11 स्टेशनों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
57.	50	बजटेतर संसाधनों के जरिए इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत की जा रही है।	कार्यान्वित
58.	52	भारतीय रेल सभी पूर्वोत्तर राज्यों को रेल कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेघालय अब भारतीय रेल के मानचित्र पर आ गया है और अरूणाचल प्रदेश को दिल्ली से सीधे कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष मार्च तक बराक घाटी को बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाएगा।	27.03.2015 को बराक वैली को बड़ी आमान से जोड़ दिया गया है।

59.	52	इस क्षेत्र के शेष राज्यों को जोड़ने के लिए कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति पर है।	अगरतला को 13.01.2016 को बड़ी आमान से जोड़ा गया है। 31 मार्च 2016 तक मिजोरम तक बड़ी लाइन की कनेक्टिविटी मुहैया करा देने की संभावना है।
60.	54	पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेट कोरिडोर का दुर्गावती – सासाराम के 55 किमी. खण्ड को चालू वर्ष में पूरा किया जाएगा।	सीआरएस से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, इसे 31 मार्च 2016 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है।
61.	54	चार अन्य डेडीकेटिड फ्रेट कोरिडोरों के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और इसे इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।	उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और पूर्व तट के लिए अध्ययन पूरे हो गए हैं। दक्षिण गलियारे के लिए अध्ययन, 31 मार्च 2016 तक पूरा होने की संभावना है।
62.	56	हमारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एन्ड-टु-एन्ड लॉजिस्टिक्स समाधान मुहैया कराने के लिए सम्हलाई तथा मूल्य संवर्द्धित सेवाओं के साथ सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाएं विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम – ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (ट्रांसलोक) स्थापित करने का प्रस्ताव है।	फाइनल कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया जा रहा है।
63.	57	हमारे किसानों के लाभ के लिए आजादपुर मंडी में अद्यतन सुविधाओं के साथ नश्य पदार्थ कार्गो सेंटर के कार्य को पूरा किया जा रहा है, जिसमें केला पकाने के लिए एक वैज्ञानिक केंद्र है।	कार्यान्वित
64.	58	प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलों (पीएफटी) के नेटवर्क को तेजी से विकसित करने के लिए 2010 में एक नीति जारी की गई थी और इसमें निजी निवेश आमंत्रित करने के लिए 2012 में संशोधन किया गया था। कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, जिनसे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलों में और निवेश प्राप्त होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। हमारा इरादा तत्काल	कार्यान्वित

		इन मुद्दों का समाधान करने का है ताकि इन टर्मिनलों की संख्या बढ़ना प्रभावित न हो।	
65.	58	हम आगामी 3 माह में प्राइवेट सेक्टर के हमारे भागीदारों के लिए अधिक उदार, व्यापक और आकर्षक बनाने के लिए माल डिब्बों को लीज पर देने की योजना, स्पेशल फ्रेट ट्रेन आपरेटर योजना, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल योजना तथा उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना की समीक्षा करेंगे।	कार्यान्वित
66.	58	हम बेहतर ईंधन दक्षता और वहन क्षमता के लिए नए और हल्के डिज़ाइन वाले वैगनों पर भी विचार करेंगे।	डिज़ाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऑसिलेशन परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे 2016-17 में भारतीय रेल के बेड़े में शामिल किया जाएगा।
67.	59	खाली मालडिब्बों की ढुलाई को कम करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण रेलवे पर अक्तूबर 2014 में एक पायलट परियोजना के रुप में परम्परागत रुप से मालडिब्बों की खाली ढुलाई होने वाली दिशा में लदान किए गए यातायात के लिए आटोमैटिक फ्रेट रिबेट स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर शुरु करने का हमारा प्रस्ताव है।	कार्यान्वित
68.	60	ऐसी लम्बी दूरी के कर्षण वाली माल गाड़ियों का परिचालन ज्यादा किया जाएगा, जिसमें दो अथवा उससे ज्यादा माल गाड़ियों को एक गाड़ी के रूप में चलाया जाता है। इसके लिए लम्बी लूप लाइनों के निर्माण की गति बढ़ाई जाएगी।	लंबे लूपों पर होने वाले खर्च को पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुणा बढ़ा दिया गया है।
69.	60	इसके अलावा, लंबी दूरी के कर्षण वाली गाड़ियों के माल डिब्बों को जिस गति से संवितरित पावर सिस्टम मुहैया कराया जाता है, उसकी भी गति बढ़ाई जाएगी।	कुछ नए इंजनों में इसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

70.	61	भारतीय रेलवे के सभी प्रमुख माल यातायात वाले मार्गों पर लदान घनत्व अपग्रेड करके 22.82 टन धुरा भार किया जाएगा।	2015-16 में लगभग 7000 किमी के लिए उच्चतर धुरा भार को अनुमोदन दे दिया गया है।
71.	62	महोदया, हम अत्यंत जोश के साथ हमारी विशेष परियोजनाओं जैसे कि मुंबई-अहमदाबाद के बीच उच्च रफ्तार की रेल गाड़ियां चलाने को जारी रखेंगे। इसके लिए व्यावहारिकता अध्ययन अंतिम चरण में है और इसकी रिपोर्टें इस वर्ष के मध्य तक प्राप्त हो जाने की आशा है। हमें रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद इस संबंध में त्वरित और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।	कार्यान्वित - नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन नामक नई कंपनी को 31 मार्च 2016 तक समाविष्ट कर लिया जाएगा।
72.	63	रेलवे के कायाकल्प में मेक इन इंडिया पहल के लिए असीम अवसर हैं। क्षमता बढ़ने के साथ-साथ, भारतीय रेल को अधिक रेलइंजनों, अधिक मालडिब्बों और अधिक सवारी डिब्बों की आवश्यकता होगी। 'बिग टिकट' विनिर्माण सुझावों में उच्च अश्व शक्ति और हरित प्रौद्योगिकी के रेलइंजन, ऑटो कैरियर जैसे विशिष्ट मदों वाले मालडिब्बे, सिगनल प्रणालियां और गाड़ी सुरक्षा प्रणालियां तथा रेलपथ बिछाने एवं रेलपथ अनुरक्षण मशीनें शामिल हैं। इन सभी के परिणामस्वरूप नौकरी के काफी अवसर उत्पन्न होंगे।	कार्यान्वित. 2 लोको फैक्टरियों के लिए निविदाएं आबंटित की गईं हैं।
73.	64	भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों और कारखानों की उनके उत्पादों के विनिर्माण में उन्हें कटिंग एज प्रदान करने के दृष्टिकोण से कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी।	डीरेका/वाराणसी और सडिका/ चेन्नै में प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन, प्रक्रिया सुधार, उत्पादकता बढ़ाने आदि के लिए अध्ययन किया गया है। रेपका/बंगलौर, डीआका/ पटियाला और रेडिका/कपूरथला द्वारा 31 मार्च 2016 तक उत्पादकता में सुधार अध्ययन शुरू करने के लिए एजेंसी को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

74.	64	इन इकाइयों की अतिरिक्त क्षमता का बाहरी ग्राहकों के लिए उपयोग किया जा सकता है।	रेडिका/कपूरथला को बंगलादेश रेलवे को 120 एलएचबी सवारी डिब्बों का निर्यात करने और रक्षा मंत्रालय के लिए 3एसी के 90 सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए आदेश प्राप्त किया है। सडिका/चेन्नै को रक्षा मंत्रालय के लिए 2एसी के 40 और 32 मिलिट्री लंगर सवारी डिब्बों के विनिर्माण के आदेश प्राप्त हुए हैं। आईसीएफ, डीआरडीओ के लिए भी 7 एकीकृत संचार कोच और 2 जेट डिफ्लेक्टर क्रेनों का विनिर्माण कर रही है। अराकू वैली और जे एंड के वैली के लिए स्पेशल सवारी डिब्बे बनाने के लिए भी आदेश प्राप्त हुए हैं।
75.	66	हम जून 2015 तक, 5 वर्षीय समवेत संरक्षा योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें वार्षिक गणना करने योग्य लक्ष्यों का उल्लेख किया जाएगा।	कार्यान्वित
76.	66	हम अप्रैल 2015 तक डॉ. काकोडकर समिति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा समिति द्वारा की गई सभी लंबित सिफारिशों की जांच करेंगे।	सभी 106 सिफारिशों की समीक्षा कर दी गई है। इनमें से अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वयनाधीन हैं।
77.	67	बिना चौकीदार वाले समपारों पर चेतावनी के लिए आईआईटी कानपुर के साथ रेडियो आधारित सिगनल डिज़ाइन परियोजना शुरू की गई है।	कार्यान्वित
78.	69	सवारी डिब्बों में आग की रोकथाम और दुर्घटना के समय सवारी डिब्बों के एक-दूसरे के ऊपर न चढ़ें इसे रोकने के लिए आरडीएसओ को नई प्रणालियां विकसित करने के लिए कहा गया है।	कार्यान्वित
79.	69	हम शीघ्र ही चुनिंदा मार्गों पर गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली और गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली लगाने का भी प्रस्ताव करते हैं।	31 मार्च 2016 तक दक्षिण रेलवे में चुनिंदा मार्गों पर टीपीडब्ल्यूएस शुरू किया जाना है।

80.	70	पटरी से उतरने के मामलों को रोकने के लिए, रेलपथों का प्राथमिक नवीकरण करते समय स्लीपर और भारी पटरियों वाली आधुनिक रेलपथ संरचना का उपयोग किया जा रहा है। वेल्डिंग की बेहतर तकनीकों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, पटरियों की जांच के लिए एनालॉग मशीनों के स्थान पर डिजिटल किस्म की मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जो अधिक विश्वसनीय हैं।	9 क्षेत्रीय रेलों में डिजीटल यूएसएफडी मशीनें चालू कर दी गई हैं। शेष क्षेत्रीय रेलें 31 मार्च 2016 तक इसे शुरू कर देंगी।
81.	71	हमारा भारतीय रेल के बिज़नेस रि-इंजीनियरी तथा नवीनता की भावना जगाने के उद्देश्य से *'कायाकल्प'* नाम से एक इनोवेशन काउंसिल स्थापित करने का इरादा है।	कार्यान्वित
82.	72	अभिनव प्रौद्योगिकीय समाधान आमंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी पोर्टल बनाने का भी हमारा इरादा है।	एनएआईआर द्वारा एक नॉलेज पोर्टल विकसित कर दिया गया है।
83.	73	हम 2015-16 में बुनियादी अनुसंधान करने के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों में चार रेलवे अनुसंधान केन्द्र खोलेंगे।	कार्यान्वित
84.	73	भारत सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न प्रदान किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारा आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी में रेलवे प्रौद्योगिकी हेतु 'मालवीय पीठ' स्थापित करने का प्रस्ताव है। रेलवे की सभी परिसंपत्तियों में उपयोग की जाने वाली नई सामग्रियों के विकास में यह पीठ सहायक होगी।	कार्यान्वित
85.	74	अनुसंधान के लिए पहचानी गई रेल परियोजनाओं को शुरू करने हेतु भारतीय रेल के प्रौद्योगिकी मिशन के भाग के रूप में निवेश में भागीदारी के आधार पर रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उद्योगों का एक संघ बनाया जाएगा।	कार्यान्वित

86.	75	हम शीघ्र ही रेलवे के लिए आईटी विज़न का अनावरण करेंगे।	श्री सोम मित्तल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया आईटी विज़न प्राप्त हो गया है।
87.	75	पार्सल एवं माल डिब्बों की ट्रैकिंग के लिए बार कोड/आरएफआईडी शुरू करना, स्वचालित पार्सल गोदाम, ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली आदि जैसी ग्राहक अनुकूल मालभाड़ा संचलन पहल शुरू की जाएंगी। गाड़ी नियंत्रण और परिसंपत्ति प्रबंधन एप्लीकेशनों में समाकलन किया जाएगा।	पार्सल प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें पार्सल बुक करते समय बार कोड का उपयोग किया जा रहा है। इसमें 44 स्टेशनों को शामिल किया गया है। अन्य 37 स्टेशनों पर हार्डवेयर लगाने का कार्य चल रहा है।
88.	76	भारतीय रेलवे प्रिवेंटिव अनुरक्षण से प्रडिक्टिव अनुरक्षण की ओर अग्रसर होने का प्रस्ताव करती है। पूरी तरह से मशीनों से एकीकृत रेलपथ अनुरक्षण करने की संभाव्यता का भी पता लगाने का प्रस्ताव है, जिससे अनुरक्षण में और दक्षता आएगी। हम रेलपथ के रूटीन जांच के लिए भी नवीनतम उपकरण लाना चाहते हैं।	रेलपथ प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित
89.	77	हम मंत्रालय में मौजूदा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) सैल को सुदृढ़ करेंगे ताकि इसे और परिणामोन्मुखी बनाया जा सके।	समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।
90.	78	संविदागत कार्यप्रणाली का मानकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा जिससे समान अवसर, प्रक्रिया का सरलीकरण और नीति की निरंतरता सुनिश्चित होगी।	4 मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट जारी किए गए हैं।
91.	79	हम अपने देश के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवा के लिए 'विदेशी रेल प्रौद्योगिकी सहयोग योजना' शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं।	फाइनल कैबिनेट नोट परिपत्रित किया जा रहा है।
92.	80	मुंबई के लिए एमयूटीपी-III शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है।	नीति आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

93.	81	हम राज्यों के साथ संकेंद्रित परियोजना विकास, संसाधन जुटाने, भूमि अधिग्रहण, परियोजना कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण रेल परियोनाओं की निगरानी के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं।	कैबिनेट से अनुमोदन मिल गया है। 6 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
94.	82	रेलों के पास परियोजनाओं का भारी बकाया है जिन्हें तीव्र गति से निष्पादित किए जाने की जरूरत है। ऐसी चिह्नित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और बड़ी संख्या में इन गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। इसके लिए रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तुलन पत्र और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।	कार्यान्वित
95.	83	सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों, जो हमारी ग्राहक हैं, की नई लाइन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।	कार्यान्वित, भारतीय रेल ने रेल परियोजनाओं के लिए कोल इंडिया, एनटीपीसी और एनएमडीसी से साझेदारी की है।
96.	84	साइडिंगों के निर्माण की समूची प्रक्रिया को सरल बनाने का हमारा विचार है।	हितधारकों से विचार-विमर्श के लिए नई साइडिंग नीति अपलोड की गई है।
97.	86	परिचालन तथा अनुरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियों के क्षेत्र में वैश्विक बैंचमार्कों की पहचान करने की कार्रवाई की जा रही है।	कार्यान्वित
98.	87	हमारा विचार परियोजनाओं के चयन संबंधी मौजूदा तंत्र में सुधार करने और परियोजना नियोजन पर निर्णय करने की प्रक्रिया में सिम्यूलेशन टूल्स को अपनाने का है।	रेलवे बोर्ड में एक डेडीकेटेड समिति का गठन करके परियोजना का मूल्यांकन शीघ्रता से किया जा रहा है। ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना (यूएसबीआरएल) के विकास के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (पीएमओएस) पूरा होने के अंतिम चरण में है।
99.	87	परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी भारतीय रेलों पर ठेका संबंधी ईपीसी प्रणाली की शुरूआत करने का प्रस्ताव है।	दिशा-निर्देश जारी किए गए। निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया।

100.	88	अपेक्षित परिणाम के लिए खर्च का पता लगा कर लेखे-जोखे की मौजूदा प्रणाली का आशोधन किया जाएगा। लागत निर्धारण संबंधी डाटा भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा जिसमें रेल लाइनों के निर्माण, संवर्द्धन, अनुरक्षण और परिचालन पर किए गए खर्च की लागत शामिल हैं। इससे उन्हें चालू करने के बाद इनका मूल्यांकन अध्ययन करने में भी सहायता मिलेगी।	उत्तर पश्चिम रेलवे में अजमेर मंडल के लिए पायलट परियोजना पूरी हो गई है।
101.	89	हम उत्पादकता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से गाड़ी परिचालन का भी आडिट करने का प्रस्ताव करते हैं।	प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।
102.	90	हम अपनी सामग्री प्रबंधन प्रणाली में पेपरलैस वर्किंग का विस्तार करने का प्रस्ताव भी करते हैं। व्यवसाय को सरल बनाने पर बल देते हुए, हम वेंडर इंटरफेस मैनेजमैंट सिस्टम के माध्यम से अपने वेंडरों को डिजिटल रूप में एकीकृत करेंगे ताकि वेंडरों को एकल खिड़की पर संपर्क किया जा सके।	कार्यान्वित
103.	93	रेलवे बोर्ड में एक वित्त व्यवस्था कक्ष की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसके लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया जाएगा।	कार्यान्वित
104.	94	रेलवे दीर्घकालीन संस्थागत निवेशकों और अन्य पार्टनरों से निवेश हासिल करने के नवीन उपाय करेगी।	कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है।
105.	95	मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करना एक गंभीर मामला है। इसे रोकने के लिए भूमि रिकार्डों का अंकीय मापन शुरू कर दिया गया है और और किसी भी किस्म के अतिक्रमण के लिए अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।	कार्य प्रगति पर है। अधिकांश रिकॉर्डों को डिजीटल कर दिया गया है। डाटा एंट्री सहित सभी लैंड प्लान 31 मार्च 2016 तक पूरे कर लिए जाएंगे। रेल परिसंपत्तियों की 20% जीआईएस मैपिंग भी पूरी हो जाएगी।
106.	96	अध्यक्ष महोदया, हम अप्रकट विज्ञापन संभाव्यता का इस्तेमाल करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर रहे हैं। इस नई नीति में कारपोरेट ब्रैंडिंग के लिए स्टेशनों तथा गाड़ियों के इस्तेमाल सहित सभी क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा।	राइटस को व्यावसायिक मीडिया मार्केट इवैल्यूएशन एजेंसी चुनने का कार्य सौंपा गया है। एजेंसी को अंतिम रूप दे दिया गया है और अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

107.	97	नारगोल तक रेल कनेक्टिविटी	डीपीआर अनुमोदित
108.	97	छर्रा तक रेल कनेक्टिविटी	डेवलेपर से डीपीआर प्रतीक्षित है।
109.	97	दीघी तक रेल कनेक्टिविटी	एसपीवी गठित
110.	97	रेवास तक रेल कनेक्टिविटी	डीपीआर अनुमोदित
111.	97	टूना तक रेल कनेक्टिविटी	जुलाई 2015 में टूना पोर्ट चालू कर दिया गया।
112.	98	हमारा बीओटी/वार्षिकी के जरिए 2500 करोड़ रु. मूल्य की परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं में वर्धा-नागपुर तीसरी लाइन, काजीपेट-विजयवाड़ा तीसरी लाइन, भद्रक-नरगुंडी तीसरी लाइन और भुज-नलिया आमान परिवर्तन शामिल है।	भद्रक-नरगुंडी के लिए कन्सलटेंट नियुक्त कर दिया गया है। नागपुर-वर्धा तीसरी लाइन के लिए कन्सलटेंट की नियुक्ति के लिए निविदा रद्द कर दी गई क्योंकि कोई भी बोलीदाता क्वालीफाई नहीं कर सका। निविदा पुन: आमंत्रित की गई थी और 03.09.2015 को खोली दी गई। इसकी जांच की जा रही है। काजीपेट-विजयवाड़ा के लिए वित्तीय कन्सलटेंट की निविदा 17.11.2015 को आबंटित कर दी गई है। भुज-नलिया के लिए जेवी के गठन के लिए राइटस ने अन्य हितधारकों का चयन किया है। राइटस द्वारा संशोधित बैंकेबिलिटी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है। नागपुर-वर्धा के लिए वित्तीय कन्सलटैंसी को 07.02.2016 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

113.	99	स्क्रैप के शीघ्र निपटान के लिए भारतीय रेलवे की स्क्रैप निपटान संबंधी नीति की समीक्षा की जाएगी।	कार्यान्वित
114.	100	मानव संसाधन ऑडिट किया जाएगा।	यह कार्य डेलॉयट को सौंपा गया है। 31 मार्च 2016 तक रिपोर्ट आने की संभावना है।
115.	100	मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक पृथक लेखांकन शीर्ष के सृजन और ईआरपी आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के विकास का भी अनुसरण किए जाने का प्रस्ताव है।	कार्यान्वित
116.	100	केंद्रित मानव संसाधन कार्यनीति के भाग के रूप में, वैश्विक मानदंडों के अनुरूप कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे।	मानदंडों की समीक्षा के लिए कार्यपालक निदेशकों सहित एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।
117.	101	हम इन कर्मचारियों के लिए व्यवहार कुशलता संबंधी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करना चाहते हैं ताकि हमारे ग्राहक सम्मानित महसूस करें।	कार्यान्वित
118.	101	अपने कर्मचारियों, विशेषरूप से रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को योग में प्रशिक्षण दिया जाएगा।	कार्यान्वित
119.	102	हम पूर्ण रूप से संपन्न विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया में हैं।	भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने के लिए पहचान की गई है। कन्सलटेंट से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।
120.	103	हम अपने कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर तथा रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए बैरकों की मरम्मत का कार्य शुरू करेंगे।	मरम्मत के लिए 32968 क्वार्टरों की पहचान की गई, जिनमें से 25246 की मरम्मत की गई। मरम्मत किए जाने वाले 278 आरपीएफ बैरकों में से 243 बैरकों की मरम्मत की गई। इसे 31 मार्च 2016 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
121.	103	हम अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार लाएंगे।	कैशलेस मेडिकल उपचार योजना तैयार की गई है। रेलों द्वारा मान्यता के लिए लगभग 500 सीजीएचएस अस्पतालों की पहचान की गई है।

122.	105	ऊर्जा संरक्षण अभियान के भाग के रूप में एलईडी प्रकाश व्यवस्था उपकरणों आदि जैसे ऊर्जा कुशल साधनों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा।	25239 एलईडी फिटिंग लगाई गईं।
123.	105	ऊर्जा की बचत करने के लिए विस्तृत ऊर्जा आडिट करने से इसमें भारी संभावना का पता चलेगा।	70 एनर्जी ऑडिट किए गए।
124.	106	थोक उपभोक्ता होने पर भी रेलवे कर्षण पावर के लिए बहुत अधिक प्रभारों का भुगतान करता है। अत: बिजली कंपनियों, पावर एक्सचेंजों और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं से बोली प्रक्रिया के जरिए किफायती दरों पर बिजली खरीदने का प्रस्ताव है। इस पहल के परिणामस्वरूप आगामी कुछ वर्षों में कम-से-कम 3,000 करोड़ रुपए की अत्यधिक बचत होने की संभावना है।	कार्यान्वित
125.	107	जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए, रेलवे के सौर मिशन के भाग के रूप में सौर उर्जा के स्रोत का विस्तार करने का इरादा है। कटरा स्टेशन में सौर उर्जा संयंत्र का काम जोरों पर है और मार्च 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।	कटरा में सोलर पावर प्लांट चालू किया गया।
126.	107	इसके अलावा, डेवलेपरों द्वारा रेलवे/निजी भूमि और रेलवे की इमारतों की छतों पर उन्हीं की लागतों पर 1000 मेगावाट के सौर संयंत्र लगाए जाएंगे जिसके लिए अगले पांच वर्षों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आर्थिक सहायता/अर्थक्षम अंतरण का वित्तपोषण किया जाएगा।	लगभग 6.5 मेगावाट के लिए आदेश जारी किए गए। छतों पर 50 मेगा वाट के सोलर प्लांट लगाने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और निविदा दस्तावेज जारी किए गए. 100 मेगा वाट के लिए 30% वीजीएफ प्राप्त हुए। जैसलमेर में 25 मेगावाट का विंड मिल पावर प्लांट चालू किया गया।
127.	108	हमने जल संरक्षण के लिए एक मिशन शुरू किया है। जल संबंधी ऑडिट करने के बाद प्रमुख जल खपत केंद्रों पर वाटर रिसाइकिलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी विस्तार किया जाएगा।	32 स्टेशनों की पहचान की गई, 24 स्वीकृत किए गए और 2 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।

128.	109	पर्यावरणप्रबंधन के लिए हमारे सभी कारखाने मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। इसका लोको शेडों और प्रमुख कोचिंग एवं वैगन अनुरक्षण डिपो में विस्तार किया जाएगा।	प्रक्रियाधीन है। कारखानों, शेड और डिपो के पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है।
129.	110	डेमू गाड़ियों को दोहरे ईंधन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।	11 डीपीसी कन्वर्ट की गई। इस वित्त वर्ष में अन्य 3 को कन्वर्ट किया जाना है।
130.	111	हम इंजनों की ध्वनि का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप लाए जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।	चिरेका द्वारा विनिर्मित किए जा रहे सभी नए एचएचपी तीन फेज़ इंजन ध्वनि की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर वाले हैं। डीज़ल इंजनों में ध्वनि स्तर का कार्य प्रगति पर है। पहले सेट की सप्लाई और फिटमेंट कार्य के जनवरी 2016 में समाप्त होने की संभावना है और मार्च 2016 तक अन्य 2 सेट तैयार होंगे।
131.	111	हम वन्य-जीवों के पर्यावरण से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता का प्रदर्शन करेंगे।	रेलपथों पर हाथियों की मृत्यु संख्या कम करने के संबंध में कार्रवाई शुरू की दी गई है।
132.	113	जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते ही हैं, भारतीय रेल अपने 21 भर्ती बोर्डों के जरिए विभिन्न कोटि के कर्मचारियों की भर्ती करती है। पारदर्शिता में एक प्रमुख पहल के रूप में दो कोटियों के लिए पायलट परियोजना के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है। इसे भविष्य में सभी किस्म की भर्तियों के लिए भी अपनाए जाने का प्रस्ताव है।	कार्यान्वित
133.	115	पारदर्शिता पर जोर देने के उद्देश्य से ई-प्रापण का विस्तार किया जा रहा है जिसमें सभी मंडलों, डिपो और कारखानों को शामिल किया जाएगा।	कार्यान्वित

134.	116	एक ऐसे तंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसे विनियम बनाने, निष्पादन संबंधी मानदंड तय करने और टैरिफ का निर्धारण करने का कार्य सौंपा जाएगा। यह लाइसेंसधारियों/निजी भागीदारों और मंत्रालय के बीच होने वाले विवादों पर भी निर्णय देगा जिसकी अपील भी की जा सकेगी।	रेल विकास प्राधिकरण पर अवधारणा नोट जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अपलोड कर दिया गया है।
135.	117	यद्यपि हम भारी बदलाव लाने की कार्य योजना पर कार्य कर रहे हैं, तथापि भारतीय रेलवे राष्ट्र के प्रति अपने व्यापक दायित्व का निर्वहन करना जारी रखेगी। इसे ध्यान में रखते हुए और हमारी सरकार के स्किल डेवेलपमेंट के प्रति उच्च प्राथमिकता को देखते हुए भारतीय रेलवे के पास उपलब्ध विशाल क्षेत्रफल और आधारभूत सुविधाएं जैसे कि स्टेशनों तथा प्रशिक्षण केंद्रों को स्किल डेवेलपमेंट के लिए उपलब्ध कराकर योगदान देगी। भारतीय रेलों में बड़ी संख्या में प्रतिभावान कर्मचारी हैं जिनकी इस राष्ट्रीय कार्य के लिए सेवाएं भी उपलब्ध हैं।	कार्यान्वित, जुलाई 2015 में कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. 53 स्थानों की पहचान की गई है।
136.	118	स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम मुख्यत: महिलाओं और युवाओं वाले स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बढ़ावा देंगे। कोंकण रेलवे (केआर) ने पिछले तीन महीनों के दौरान तीन राज्यों में इस कार्यक्रम को पहले ही शुरू कर दिया है। कोंकण रेलवे को इस योजना से और पर्यटन गाइड योजना से भी आगामी कुछ वर्षों में लगभग 50,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने की आशा है।	कार्यान्वित
137.	119	हमने ऑटोरिक्शा तथा टैक्सी चालकों को पर्यटन गाइडों के रूप में प्रशिक्षित करके कोंकण रेलवे में पर्यटन का प्रोत्साहन देने का एक सफल प्रयोग किया है क्योंकि सबसे पहले वे ही यात्रियों	1000 से अधिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है।

		के संपर्क में आते हैं। हमारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इस सुविधा की व्यवस्था करने का विचार है।	
138.	121	इस अवसर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को चलाया जाएगा।	कार्यान्वित, 29.09.2015 से मदुरै और 02.10.2015 से जबलपुर में विभिन्न गांधी सर्किटों पर स्पेशल पर्यटन गाड़ियां चलाई गई हैं।
139.	121	नई खेती और विपणन तकनीक के बारे में किसानों की सहायता के लिए आईआरसीटीसी एक विशेष यात्रा योजना, किसान यात्रा पर कार्य करेगी।	कार्यान्वित, 23.09.2015 को मदुरै से भोपाल तक किसान यात्रा स्पेशल गाड़ी चलाई गई है। कर्नाटक से भोपाल के विभिन्न भागों के लिए आठ किसान यात्रा स्पेशल गाड़ियां भी चलाई गई हैं।

******